छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 292 ■ अम्बिकापुर, बुधवार 18 नवम्बर 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

'कबरा कान हाथी' का रेस्क्यू पांचवें दिन भी फेल, कुमकी पर भी पड़ा भारी

ग्रामीण रतजगा करने मजबूर, वनभोज करके विभागीय अमला सफलता का कर रहा इंतजार





छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कबरा कान हाथी का रेस्क्यू अभियान का पांचवां दिन बीत गया। वन विभाग की पूरी टीम जंगल के अंदर-बाहर तैनात है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। दिन-रात रेस्क्यू में जुटे विभागीय अमले का जंगलों में ही वनभोज चल रहा है।

वन विभाग के अनुसार, टीम 12 नवंबर को मौके पर पहुंची थी। शुरुआत में सायर नाम के जंगल में कबरा कान 17 अन्य हाथियों के साथ मिला था। कुल 18 हाथियों का दल लगभग दो दिन तक वहीं रहा, इसके बाद वह रामगढ़ इलाके के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में शिफ्ट हो गया। अब हाथियों का दल सरमा-चकेरी और तेंदूटिकरा के जंगलों में दो अलग-अलग दलों में विचरण कर रहा है। बीते सोमवार को कुमकी हाथियों की एक बार कबरा कान से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन कबरा कुमकी पर भारी पड़ गया। न तो इंजेक्शन लगाया जा सका और न ही ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल संभव हो सका। वन विभाग कुमकी हाथियों के माध्यम से उसे ड्राइव करके बाहर लाने की सोच रहा था, लेकिन झुंड के साथ घने जंगलों में छिपे होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की तरफ से जंगल के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है, हाथी बार-बार खेतों में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसल बचाने और जान-माल की रक्षा के लिए लोग रातभर आग जलाकर और शोर मचाकर जाग रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग सिर्फ आश्वासन और रोक-टोक के बजाय जल्द से जल्द कबरा कान को पकड़कर गांव से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, ताकि गांव वाले चैन से रह सकें और बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें।

सीसीएफ ने कहा, सुरक्षा पहली प्राथमिकता

सीसीएफ, वन विभाग अंबिकापुर प्रणय मिश्रा ने बताया कि रेस्क्यू अभियान जारी है और टीम पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कल दो-तीन बार एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन वेटनरी टीम हाथी को चोट न पहुंचे, झुंड के सदस्यों को कोई डिस्टर्बेंस न हो और टीम व कुमकी हाथियों की सुरक्षा बनी रहे, इस बात का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि अगर सिंगल हाथी बाहर निकलता है तो रेस्क्यू जल्दी हो जाता है, लेकिन जब हाथी झुंड के साथ होता है, जिसमें मादा और बच्चे भी हों, तो ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब तक कॉलरिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक यह अभियान चलता रहेगा। प्रणय मिश्रा ने कहा कि झुंड के साथ आने के बाद कबरा कान के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला है। थर्मल ड्रोन से निगरानी में वह पहले से ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, लेकिन झुंड में थोड़ी समस्या भी पैदा कर रहा है। फिर भी झुंड को मादा लीड करती है, इसलिए उसका व्यवहार थोड़ा पॉजिटिव दिशा में माना जा रहा है।

जंगल में ही कैंप, 100 स्टाफ तैनात

रेस्क्यू के लिए पहले उदयपुर में कैंप था, बाद में उसे रामगढ़ में शिफ्ट किया गया। वहां तीन वेटनरी डॉक्टरों की पूरी टीम, महावत और लगभग 100 स्टाफ तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर रात में सड़कों पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि हाथी के सड़क पर आने की संभावना पर लोगों को सुरक्षित किया जा सके। सीसीएफ ने कहा, हाथी जंगल के अंदर है, सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, हाथी बाहर नहीं आ रहा है, यह पॉजिटिव है। हमें कोई टाइम लिमिट का प्रेशर नहीं देना है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों और हाथी दोनों के लिए अच्छा हो।

भैंस को मारा, फसलें हो रही बर्बाद

इधर आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की तरफ से किसी को भी जंगल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हाथियों का दल आसपास के खेतों में घुसकर धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। बीती रात एक दल के हाथी ने चकेरी बस्ती में घुसकर एक भैंस को मार डाला। इस घटना से ग्रामीण भयभीत हैं और रातभर जागरण करने को मजबूर हैं। ग्राम सरमा निवासी पीला राम चरवाहा ने कह हाथियों का डर इतना है कि पिछले तीन दिनों से गांव में कोई भी रात को चैन से नहीं सो पा रहा है। पूरा गांव रातभर जागकर पहरा दे रहा है। उन्होंने बताया कि हाथियों का दल खेतों और बस्ती के आसपास घूम रहा है। बीती रात चकेरी बस्ती में एक भैंस को मारने के बाद से डर और बढ़ गया है।

पिकनिक मनाने में व्यस्त वन विभाग

कबरा कान हाथी के रेस्क्यू को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाथी पिछले 10 दिन से गांव के आसपास घूम रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के बजाय पिकनिक मनाने में व्यस्त है। हालांकि वन अमले की मजबूरी है कि वो कैंप लगाकर कबरा कान हाथी को रेस्क्यू करने में सफलता मिले, इस इंतजार में है। जंगल में डटी टीम के लिए खाने की व्यवस्था को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों का नजरिया बदल गया है। ग्रामीण का यह भी आरोप है कि जब भी गांव वाले हाथी को भगाने या आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, तो विभाग के लोग उन्हें ही चुप करा देते हैं, कहते हैं हम हाथी को पकड़ लेंगे। इसके पीछे वन विभाग का तर्क ग्रामीणों की जान को जोखिम से बचाना है।

एएसपी राजेश देवांगन ने संभाला पदभार, मिली अहम जिम्मेदारियां

नशा और ट्रैफिक पर होगा सबसे ज्यादा फोकस



छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पदोन्नति के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन ने सरगुजा जिले में पदभार ग्रहण कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश देवांगन (बैच-2015) को पदोन्नति के बाद सरगुजा जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। पदभार ग्रहण करते ही डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एएसपी राजेश देवांगन अंबिकापुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के थानों की निगरानी करेंगे।

पदोन्नति के बाद जिले में पहली पदस्थापना

एएसपी राजेश देवांगन ने कहा कि पदोन्नति के बाद इस जिले में यह उनकी पहली पदस्थापना है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दीं। उनका सबसे ज्यादा फोकस नशे के कारोबार और बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा। उन्होंने कहा कि जिले में नशे को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आम जनता नशे से परेशान है। उनकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि नशे के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई हो। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना भी प्राथमिकता

एएसपी ने कहा कि शहर लगातार बढ़ रहा है और भीड़भाड़ भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करना जरूरी है। गलत पार्किंग और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा, ताकि आम लोगों को जाम और दुर्घटना से राहत मिल सके।

अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों को कवच प्रदान करने कांग्रेस आगे आए

मुस्लिम संगठनों ने समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात



छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर रजा यूनिटी फाउंडेशन अंबिकापुर की पहल पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामी शरीयत में संभावित हस्तक्षेप और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मांग की है कांग्रेस पार्टी विधानसभा में इस बिल के खिलाफ प्रभावी ढंग से आवाज उठाए और अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। प्रतिनिधियों ने कहा कि समानता और न्याय के नाम पर किसी भी समुदाय के धार्मिक अधिकारों, व्यक्तिगत कानूनों एवं संवैधानिक स्वतंत्रता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ऐसे संवेदनशील विषय पर संबंधित समुदाय की राय और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। रजा यूनिटी फाउंडेशन की ओर से कहा गया कि संगठन मुस्लिम समाज के धार्मिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। संगठन ने उम्मीद जताई है कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की मजबूती के लिए पुरजोर प्रयास करेगी और यूसीसी बिल का विरोध कर अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों को कवच प्रदान करेगी। टीएस सिंहदेव ने यूसीसी बिल से अल्पसंख्यक समाज को होने वाली संभावित परेशानियों के प्रति चिंता जाहिर की और पार्टी फोरम व अन्य जगहों पर इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया।

मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से रजा यूनिटी फाउंडेशन के संस्थापक शादाब आलम रिजवी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इकबाल अंसारी, अधिवक्ता नौशाद सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी, जिलानी खान, रशीद अंसारी, रहमत खान, फैजान अहमद, एडवोकेट युसूफ अहमद, मोहम्मद असलम, शहजाद अली, शेख रकीब अंसारी, तबरेज अंसारी, बउआ इश्तियाक, शाहजेब अंसारी, रकीब गुलजार, अनवर खान, मेराज अंसारी, शिफ्टेन रजा, गुलाब खान, एवं हाजी लुकमान सहित मुस्लिम समाज के विभिन्न इदारों एवं संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

लोन सेटलमेंट के नाम पर 6.10 लाख लेकर जमा नहीं किया

शिकायत पर गांधीनगर थाने में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज



छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। लोन खत्म कराने का झांसा देकर एक परिचित युवक ने पति-पत्नी से 6 लाख 10 हजार रुपये ठग लिए। आरोपी ने पैसे लेकर कहा कि दोनों लोन सेटल हो गए हैं, लेकिन हकीकत में उसने बैंक या फाइनेंस कंपनी में एक रुपया भी जमा नहीं किया। जब कंपनी से बकाया किस्त के लिए फोन आया, तब दंपती को ठगी का पता चला। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता शकुंतला टोप्पो ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी प्रतीक ठाकुर के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, शकुंतला टोप्पो के पति इग्नासियुस टोप्पो ने वर्ष 2023 में एक्सिस बैंक से 5.50 लाख रुपये और चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से 7.64 लाख रुपये लोन लिया था। किस्तें समय पर जमा नहीं होने से ब्याज बढ़ता जा रहा था, जिससे दंपती परेशान थे। इसी दौरान महिला के पति का परिचित प्रतीक ठाकुर 13 मार्च 2025 को उनके घर पटपरिया पहुंचा। उसने कहा कि वह दोनों लोन का सेटलमेंट करवा देगा और रकम जमा कर देगा। पुरानी पहचान होने के कारण दंपती ने उस पर भरोसा कर लिया। पुलिस मामले की जांच के साथ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी।

किश्तों में दिए 6.10 लाख रुपये

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, दंपती ने उसी दिन आरोपी को 2 लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद 7 जुलाई 2025 तक अलग-अलग किश्तों में ऑनलाइन और चेक के माध्यम से 4 लाख 10 हजार रुपये और दिए। इस तरह कुल 6 लाख 10 हजार रुपये आरोपी को सौंप दिया। रकम लेने के बाद आरोपी ने कहा कि दोनों लोन सेटल हो गए हैं, लेकिन उसने न तो कोई रसीद दी और न ही कोई दस्तावेज दिखाया। पूछने पर वह लगातार बहाने बनाता रहा।

कंपनी के फोन से खुला राज

कुछ दिन पहले चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से इग्नासियुस टोप्पो के पास बकाया राशि जमा करने के लिए फोन आया। यह सुनकर दंपती हैरान रह गए, उन्हें लग रहा था कि लोन खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोपी से संपर्क किया तो उसने फिर से जल्द लोन क्लियर कराने का आश्वासन दिया, लेकिन पैसे जमा नहीं किए। अंत में ठगी का अहसास होने पर महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि शकुंतला टोप्पो आयुष विभाग में सक्ती जिले में पदस्थ हैं, जबकि उनके पति पंचायत सचिव हैं।

बेजुबानों को बोरी में भरकर जलाने के मामले में केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पंजाब गार्डन के पीछे बीते 13 नवंबर की शाम करीब 4.30 बजे बेजुबान कुत्ते के पिल्लों को बोरी में भरकर, क्रूरता पूर्वक जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से बेजुबान डॉग शेल्टर के संचालक सुधांशु शर्मा निवासी दर्रीपारा को मिली थी। इसके बाद 15 नवंबर को सुधांशु शर्मा ने थाना गांधीनगर में लिखित आवेदन देकर घटनाक्रम से अवगत कराया था। यह घटना न केवल पशु क्रूरता की पराकाष्ठा, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा के साथ ही आक्रोश का माहौल भी पैदा करने वाला था। पुलिस ने शिकायत पर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ठ) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में दोषियों की पहचान की है, इनमें कम उम्र के लोगों के शामिल होने जैसी बातें सीसीटीव्ही फुटेज को खंगालने के बाद सामने आई थी। भविष्य में ऐसी अमानवीय घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे देखते हुए शेल्टर के संचालक ने दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गई है।

चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत 21 को

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। चेक बाउंस के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर द्वारा 21 नवंबर, शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार यह अदालत अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर के मार्गदर्शन में आयोजित होगी। इस विशेष लोक अदालत में केवल 'परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण (चेक बाउंस) के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चेक बाउंस प्रकरणों से जुड़े सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, सक्रिय सहभागिता निभाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर आयोजन को सफल बनाएं। अधिक जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के लिए नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर अथवा तालुका विधिक सेवा समिति सीतापुर सहित जिले की संबंधित तालुका विधिक सेवा समितियों में संपर्क कर सकते हैं।

पक्षकारों से सक्रिय सहभागिता का आग्रह-प्राधिकरण ने बताया कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्रवाई से मुक्ति मिलती है, समय की बचत होती है और आपसी विवादों का सौहार्द्रपूर्ण समाधान हो पाता है। प्राधिकरण के अनुसार विशेष लोक अदालत केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विवादों को आपसी सहमति से समाप्त करने तथा समय एवं संसाधनों की बचत करने का एक प्रभावी माध्यम है।

अस्पताल जाने निकली महिला मासूम बच्ची के साथ लापता

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। दरिमा थाना क्षेत्र से एक महिला अपनी बच्ची को लेकर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर जाने की बात कहकर निकली, इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। पति ने अपहरण का संदेह जताते हुए इसकी रिपोर्ट दरिमा थाने में दर्ज कराई है।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम सोहगा निवासी मजदूर दिलीप कुमार वैष्णो ने पुलिस को बताया है कि वह सुबह अपनी बड़ी बेटी सरिता वैष्णो को शासकीय प्राथमिक शाला सोहगा में छोड़कर काम करने के लिए डांडपारा करजी गया था। सुबह 9.56 बजे उसकी 26 वर्षीय पत्नी का फोन आया कि कमर-पीठ में दर्द हो रहा है, इलाज के लिए छोटी बेटी को लेकर जिला अस्पताल अंबिकापुर जा रही है। इसके बाद 10.30 बजे दिलीप ने पत्नी के मोबाइल में फोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। अंबिकापुर, आसपास के गांव और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन के बाद भी पत्नी और बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी, अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

केंद्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर में 20 को लगेगा स्वास्थ्य शिविर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। वी केयर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल द्वारा 20 नवंबर शुक्रवार को केंद्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर में नि:शुल्क सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।शिविर में तीन प्रमुख विशेषज्ञ विभागों के चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। न्यूरोसर्जरी विभाग में मस्तिष्क एवं नसों संबंधी रोगों का परीक्षण और सलाह उपलब्ध रहेगी। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में हड्डी एवं जोड़ों की समस्याओं का परामर्श मिलेगा, जबकि यूरोलॉजी विभाग में मूत्र एवं गुर्दा संबंधी रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर में नि:शुल्क बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी जांच की सुविधा भी दी जाएगी। यह जांच हड्डियों की मजबूती का आकलन करने में सहायक होती है।अस्पताल प्रबंधन ने अपील की है कि वे इस नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं।

जिले में अब तक 16,288 क्विंटल धान की खरीदी, 54,019 किसान पंजीकृत

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जिले में सुचारु रूप से जारी है। 16 नवंबर तक की स्थिति में जिले के उपार्जन केंद्रों में कुल 16,288 क्विंटल मोटा धान खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक खरीदी वीरेंद्रनगर केंद्र में हुई है, जहां 1,196 क्विंटल धान खरीदा गया। इसके बाद भंवरमाल में 1,144, महराजगंज में 979.60, त्रिकुंडा में 882.80, विजयनगर में 858 तथा बसंतपुर में 811.20 क्विंटल धान की खरीदी के साथ अन्य धान उपार्जन केन्द्रों में भी सुगमतापूर्वक से धान की खरीदी की जा रही है।

धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने कलेक्टर ने ली बैठक

हाट-बाजार से लेकर चेकपोस्ट तक अवैध धान पर कड़ी निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही खरीदी के निर्देश



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज धान खरीदी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि खरीदी पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जिले के उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों का धान ही खरीदा जाए।

जिले के 14 संवेदनशील और 9 अति संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में उपयुक्त वरिष्ठता वाले प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को खरीदी प्रभारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने इन अधिकारियों को बिचौलियों और कोचियों के धान पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाट-बाजारों से लेकर स्थानीय स्तर तक होने वाली हर अनियमितता को ट्रैक किया जाए। अवैध धान भंडारण, संग्रहण और परिवहन को रोकने के लिए बैरियर और चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों में जब्त किए गए धान की एंट्री अनिवार्य रूप से कराई जाए।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदने से पहले उसका गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए और केवल निर्धारित मानक मापदंडों के अनुरूप धान ही खरीदा जाए। मापदंडों के अनुसार धान में नमी अधिकतम 17 प्रतिशत, अकार्बनिक व कार्बनिक विजातीय पदार्थ 1-1 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने दाने 5 प्रतिशत, अपरिपक्व व सिकुड़े दाने 3 प्रतिशत तथा निम्न श्रेणी के धान का मिश्रण अधिकतम 6 प्रतिशत तक ही मान्य है।

खरीदी के नियमित पर्यवेक्षण के लिए जिले के सभी 54 उपार्जन केंद्रों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो केंद्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बैठक में समितियों में हमालों की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई, और हर समिति में हमाल पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने के निर्देश दिए गए।

चेकलिस्ट के अनुसार हर केंद्र के लिए नामांकित सत्यापनकर्ता अधिकारी केंद्रों की तैयारियों की जांच कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर और यूपीएस की कार्यशील स्थिति, समतल और ऊंचे स्थल पर धान का सुरक्षित भंडारण तथा पॉलिथीन कवर, डनेज, सीमेंट ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक्स की उपलब्धता देखी जा रही है। साथ ही आर्द्रतामापी यंत्रों का कैलिब्रेशन और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। जहां आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं हैं, वहां समितियों को नए यंत्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार सिदार, खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम, जिला विपणन अधिकारी सुश्री प्रीतिका पूजा केरकेट्टा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बिश्रामपुर में तैयार हो रही आवासीय वॉलीबॉल अकादमी

बच्चों को पढ़ाई के साथ मिलेगा खेल प्रशिक्षण



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिश्रामपुर में आवासीय वॉलीबॉल अकादमी तैयार की जा रही है। वॉलीबॉल एसोसिएशन की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा अयप्पा ग्राउंड में वॉलीबॉल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसके शुरू होने की उम्मीद है।

डीएमएफ मद से निर्मित हो रहे इस वॉलीबॉल मैदान के लिए 11.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। निर्माण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास परियोजना संभाग को सौंपी गई है। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय परिसर में तैयार हो रहे इस मैदान का निर्माण पूरा होने के बाद वॉलीबॉल में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी।

अकादमी के माध्यम से बच्चों को खेल की बारीकियों का प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी। मैदान का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आगामी कुछ दिनों में अकादमी का शुभारंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

बेटियों की गरिमा और स्वच्छता की ओर कदम: कोरवापारा स्कूल में बालिका शौचालय का लोकार्पण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जनपद पंचायत राजपुर की ग्राम पंचायत बैढी के पूर्व माध्यमिक शाला कोरवापारा में आज बालिका शौचालय का लोकार्पण किया गया।

जनपद अध्यक्ष श्री विनय भगत की उपस्थिति में स्कूल की छात्राओं ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश तथा जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी के मार्गदर्शन



में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) के तहत जनपद पंचायत राजपुर में 43 बालिका शौचालय बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने VB-G RAM G पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती सुंदरमुनि मिंज, जनपद सीईओ श्री संजय दुबे, सरपंच श्री ईसु कुजूर, प्रधान पाठक श्री श्याम सुंदर चौरगे सहित जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी, पंचगण, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

स्टेशन मास्टर का मोबाइल हैक कर दोस्तों से मांगे पैसे, 40 हजार की साइबर ठगी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। साइबर ठगी रोकने पुलिस के लगातार जनजागरूकता अभियान चलाने के बावजूद ठगी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामले में साइबर ठगों ने करंजी रेलवे स्टेशन मास्टर पीके श्रीवास्तव का मोबाइल हैक कर उनके परिचितों और दोस्तों को इमरजेंसी मैसेज भेजकर 40 हजार रुपए की ठगी कर ली है। ठगी के शिकार सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मी राम श्रृंगार पांडेय ने बिश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि करीब चार दिन पहले साइबर ठगों ने स्टेशन मास्टर पीके श्रीवास्तव का मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद उनके संपर्क सूची में शामिल लोगों को अति आवश्यक बताकर रुपए भेजने के मैसेज किए जाने लगे। मैसेज देखकर कई लोगों ने स्टेशन मास्टर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल नहीं लग सका। इसी दौरान उनके मित्र एवं सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मी राम श्रृंगार पांडेय ने ठगों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर अपने खाते से 40 हजार रूपए ट्रांसफर कर दिए। यह रकम 25 हजार और 15 हजार रुपए की दो किस्तों में भेजी गई, जिसे ठगों ने तत्काल निकाल लिया। इसी दौरान एक अन्य युवक ने भी स्टेशन मास्टर के नाम पर 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन उसने ठगों के बताए क्यूआर कोड के बजाय सीधे स्टेशन मास्टर के बैंक खाते में रकम जमा कर दी। इस वजह से उसके 50 हजार रुपए सुरक्षित बच गए। बाद में स्टेशन मास्टर के मित्रों ने उनके दूसरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर रुपए मांगने की वजह पूछी, तब मोबाइल हैक होने और साइबर ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने तत्काल अपना बैंक खाता लॉक कराया। अगले दिन दो लोगों द्वारा रुपए भेजे जाने की जानकारी मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विधानसभा सत्र के लिए जिला कार्यालय में विधानसभा सेल गठित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 14 से 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान आने वाले विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, आश्वासनों और अन्य विषयों की जानकारी तय समय में शासन को भेजने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिला कार्यालय में विधानसभा सेल गठित किया है।

आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल को नोडल अधिकारी और अधीक्षक श्री संजय कुमार मरई को विधानसभा सेल का प्रभारी बनाया गया है। श्री राजदेव सिंह और श्री विकास बखला सेल में सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

वीएसके ऐप में ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर हुई कार्रवाई

29 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों का नवंबर का वेतन भी रोका

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन.के. निरापुरे ने कड़ी कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ 29 कर्मचारियों की आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। इनमें शंकरगढ़ के 5, रामचंद्रपुर के 3, राजपुर के 5, बलरामपुर के 4, कुसमी के 6 और वाड्रफनगर के 6 कर्मचारी शामिल हैं। कार्रवाई की जद में प्रभारी प्राचार्य, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य संवर्ग के कर्मचारी आए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत की गई है। ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित नहीं करने पर संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है, और उनका नवंबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री निरापुरे ने कहा कि शासकीय सेवा में अनुशासन, समयबद्धता और जवाबदेही सर्वोपरि है, और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रमुखों को अपने अधीन कर्मचारियों की प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा कर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विधानसभा सत्र के चलते 17 दिसंबर तक अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसे देखते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर 17 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस अवधि में सभी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।

अपरिहार्य स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति से अवकाश ले सकेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों को अवकाश के लिए कलेक्टर से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक भूख शुरू

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक बिश्रामपुर क्षेत्र द्वारा ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर 17 नवंबर से महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। संघ के क्षेत्रीय सचिव पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि विश्रामपुर क्षेत्र की विभिन्न खदानों में कार्यरत सैकड़ों ठेका श्रमिकों द्वारा गत दिनों 5 अक्टूबर को ग्राम पंचायत पोड़ी के ग्राउंड से रैली निकालकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया था।



बावजूद इसके क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की जायज मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच 5 नवंबर को हुई वार्ता में भी श्रमिकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल सका और वार्ता विफल रही।

प्रबंधन के इसी उदासीन रवैये के विरोध में संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज 17 से 24 नवंबर तक क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिसमें आज पहले दिन ठेका श्रमिक संत लाल, रामकृपाल, रामचंद्र, राम प्रसाद, ईश्वर, बुद्धि सिंह, अमन सिंह, रामकुमार, रामेश्वर सिंह, श्याम लाल भूख हड़ताल पर बैठे रहे। संघ का कहना है कि यदि निर्धारित अवधि में भी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की मांग है कि सभी खदानों में कार्य समिति का अनिवार्य गठन किया जाए। सभी ठेका श्रमिकों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाए।कोयला ट्रांसपोर्ट, साइडिंग, सोलर प्लांट एवं खान परिसर के सभी कामगारों को एचपीसी वेज का भुगतान हो। बायोमेट्रिक व उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी दर्ज हो एवं प्रति माह 26 दिन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और अनिवार्य वेतन पर्ची दी जाए। कॉरपोरेट बैंक खातों से वेतन भुगतान हो ताकि श्रमिकों को कॉरपोरेट बीमा का लाभ मिल सके। बोनस/पीएलआई का पूर्ण भुगतान हो तथा गायत्री एवं केतकी खदान के वर्ष 2024-25 का बकाया बोनस तुरंत दिया जाए। खदानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो और दुर्घटनाओं को छुपाने की प्रथा पर तत्काल रोक लगे।

गायत्री एवं केतकी खदान के आसपास रोजगार के नाम पर हो रही अवैध धन उगाही की उच्चस्तरीय जांच कराकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। पूर्व में वेतन से काटी गई सीएमपीएफ राशि की तत्काल वापसी या समायोजन किया जाए।

डीईओ ने स्कूलों का किया आकस्मिक निरीक्षण, पण्डोपारा में दो शिक्षक मिले गैरहाजिर

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन.के. निरापुरे ने जिले के विभिन्न विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति, शैक्षणिक व्यवस्था और पाठ्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण में प्राथमिक शाला पण्डोपारा के प्रधान पाठक श्री सुदेश्वर समट और सहायक शिक्षक श्री गणेश राम राठिया अनुपस्थित पाए गए। दोनों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश दिए गए। प्राथमिक शाला गौरापारा, चम्पापुर, कोदाकी और चन्दोरा में शिक्षक उपस्थित मिले। हाई स्कूल भेंडरी में उन्होंने शिक्षकों को निर्धारित समय में पाठ्यक्रम



पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर श्री निरापुरे ने धान खरीदी केंद्र रनहत का भी निरीक्षण किया और मानक के अनुरूप खरीदी तथा किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की समय पर उपस्थिति और नियमित अध्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोनगरा में तिलक-पुष्पहार से हुआ अन्नदाताओं का सम्मान, शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में 16 नवंबर को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सोनगरा के धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना एवं किसानों के सम्मान के साथ धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक शरद चंद्र द्विवेदी ने किसानों का तिलक लगाकर, गले में पुष्पहार पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत और सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने धान



खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। धान खरीदी के पहले ही दिन सोनगरा उपार्जन केंद्र में किसानों का अच्छा उत्साह देखने को मिला। शुभारंभ दिवस पर कुल 7 किसानों से 200 क्विंटल 40 किलोग्राम धान की खरीदी की गई। इस दौरान उपार्जन केंद्र पहुंचे किसानों के साथ मुख्य अतिथि ने संवाद किया और धान खरीदी प्रारंभ होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। किसानों के सम्मान के साथ खरीदी की शुरूआत ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।

किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार प्रतिबद्ध ङ्घ शरद चंद्र द्विवेदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक शरद चंद्र द्विवेदी ने कहा कि किसान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। किसानों की मेहनत से ही प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न निर्णय ले रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास कर रही है। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुचारु संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

ऑनलाइन टोकन कटवाकर निर्धारित प्रक्रिया से बेचें धान

द्विवेदी ने क्षेत्र के किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान धान विक्रय के लिए समय पर ऑनलाइन टोकन अवश्य कटवाएं तथा निर्धारित तिथि पर अपने धान को उपार्जन केंद्र में लेकर आएं। शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का विक्रय करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्र में आने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया।

किसानों के सम्मान के साथ शुरू हुई खरीदी

सोनगरा धान उपार्जन केंद्र में खरीदी के शुभारंभ अवसर पर किसानों के माथे पर तिलक, गले में पुष्पहार और मिठाई खिलाकर सम्मानित करने की पहल ने किसानों के प्रति सम्मान और आत्मीयता का संदेश दिया। पहले दिन 7 किसानों से 200 क्विंटल 40 किलोग्राम धान की खरीदी के साथ केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष की शुरूआत हुई। धान खरीदी प्रारंभ होने से सोनगरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। धान खरीदी शुभारंभ कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला विशेष आमंत्रित सदस्य दशरथ सिंह, सोसायटी अध्यक्ष भोला सिंह, जनपद सदस्य राजेश पोर्ते, सरपंच कृष्णा सिंह, जिला कार्यसमिति सदस्य सहकारिता प्रकोष्ठ लालसाय नेताम, मनोहर जायसवाल, समिति प्रबंधक तनवीर आलम खान, गिरधारी राजवाड़े, खेम सिंह, सिद्धार्थ मिश्रा एवं मूलधर सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, किसान एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दम्पत्ति को 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन की अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सरगुजा जिले के एक दम्पत्ति को 2 लाख 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम बिलासपुर, थाना एवं तहसील बतौली, जिला सरगुजा निवासी अमन कुमार सरसोसिया एवं बिलासपुर निवासी श्रीमती श्रेया शर्मा को योजना के तहत यह राशि स्वीकृत की गई है। नियमानुसार स्वीकृत राशि में से 1 लाख रुपये दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1 लाख 50 हजार रुपये दम्पत्ति एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखे जाएंगे।

पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर महासंघ ने बीएसए को दिया ज्ञापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बाबागंज, बहराइच। जनपद में गतिमान बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और शासनादेश व पूर्व के नियमों के अनुरूप संपादित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच (बीएसए) को आठ सूत्रीय मांग पत्र दिया है। महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पूर्व के नियमों के विपरीत पदोन्नति प्रक्रिया संपादित की गई तो महासंघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र के नेतृत्व में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) के निदेर्शानुसार पदोन्नति प्रक्रिया दिनांक 7 नवंबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी, लेकिन जनपद में यह अब तक अधूरी है। मांग पत्र में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक 12 नवंबर 2026 के पत्र के क्रम में स्पेशल टीईटी परीक्षा में सम्मिलित शिक्षकों का परीक्षा परिणाम आने तक उनके पद सुरक्षित रखने का निर्देश है। अतः जनपद के सभी विकास खंडों से सूचना मंगाई जाए कि किन शिक्षक, शिक्षिकाओं ने किस स्तर (प्राथमिक या उच्च प्राथमिक) की स्पेशल टीईटी परीक्षा दी है, पूर्व से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, शिक्षिकाओं से जनपद के समस्त रिक्त विद्यालयों में से एक विद्यालय का विकल्प चुनने के उपरांत शेष बचे विद्यालयों में से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च प्राथमिक/प्राथमिक स्तर के केवल उतने ही पद सुरक्षित किए जाएं जितनी आवश्यकता है,

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निदेर्शानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से 02 से 17 नवंबर 2026 के मध्य संस्था स्तर, विधानसभा स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में 17 नवम्बर को विधानसभा से चयनित शीर्ष 10-10 छात्र-छात्राओं के मध्य संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर में जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका निरीक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार देवांगन द्वारा किया



गया। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी एवं विद्यार्थियों से अपील किया कि ऐसे छूटे हुए विद्यार्थी जो 17 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे भावी मतदाता के रूप में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं तथा उनके घर या आसपास के जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र विद्यार्थी युवा हों, उनका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से स्वयं एवं ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से फार्म-06 लेकर भरा जाए। जिला परियोजना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (स्वीप) गिरीश गुप्ता ने जानकारी दी कि विधानसभा स्तर से दोनों विधा में कुल 60 (30-30) विद्यार्थी चयनित होकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें जिला स्तर से चयनित शीर्ष 10-10 छात्र-छात्राओं की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाएगी। साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित निबंध प्रतियोगिता का विषय ₹मतदान का महत्व₹ तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय ₹मतदाता सूची तैयार करना, ईवीएम और वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया₹ रखा गया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक की जागरूकता और मतदान में सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है।

परिवार पर जानलेवा हमला, मां-बेटे समेत चार घायल

मोहनलालगंज। मोहनलालगंज के रानीखेड़ा डेहवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया हमले में मां-बेटे समेत चार लोग घायल हो गए मां और बेटे के सिर में गंभीर चोटें आने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी पीड़ित संदीप यादव की तहरीर के अनुसार 13 नवंबर की सुबह करीब सात बजे रामेश्वर उसके पुत्र लवकुश व रोहित यादव सुमन और पुष्पा निवासी गहरू थाना सरोजनीनगर एकराय होकर उनके घर पहुंचे और उनकी मां रामजानकी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया मां को बचाने पहुंचे संदीप यादव उनके भाई आजाद यादव और बहन नेहा के साथ भी मारपीट की गई

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया गया केन्द्रीय जेल का निरीक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनपुर। केन्द्रीय जेल अंबिकापुर जिला सरगुजा का निरीक्षण किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया गया, जहां पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का सत्यापन किया गया एवं उनसे पूछताछ की गई। निरीक्षण में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती देवन्ती साहू, सदस्य श्रीमती रानु पांडेय, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सुमंती खाखा, काउंसलर एवं परामर्शदाता राखी तिवारी, आउट रीच वर्कर सुशील यादव और सामाजिक कार्यकर्ता एवं छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर जिला सरगुजा के प्रदेश सचिव सुरेन्द्र साहू रहे। निरीक्षण के दौरान जेल में बंद महिलाओं से भी मुलाकात एवं चर्चा कर उनकी समस्याओं के



बारे में जानकारी एकत्र की गई। इस दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने 18 वर्ष के आसपास के बालकों से उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जो बालक 18 वर्ष से कम उम्र के लगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और उनकी फाइल को किशोर न्याय बोर्ड में भेजने का निर्देश दिया। निरीक्षण में केन्द्रीय जेल के अधीक्षक सहित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय जेल के पाकशाला का निरीक्षण भी किया गया।

सांसद चिंतामणी महाराज के मुख्य आतिथ्य में होगा जनजातीय गौरव दिवस समारोह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले में 18 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम हॉल अंबिकापुर में दोपहर 12:00 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, सरगुजा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देव नारायण यादव, अम्बिकापुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण

समारोह के दौरान कई प्रमुख सांस्कृतिक एवं सम्मान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जनजातीय शहीद परिवारों एवं समाज प्रमुखों का विशेष सम्मान किया जाएगा। जिला स्तरीय जनजातीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें क्राफ्ट, कला, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन, वाद्य यंत्र, रंग, शौर्य, औषधी और पुस्तक मेले का प्रदर्शन होगा। लोक नृत्य कलाकारों तथा चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समारोह में आकर्षक लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

राज्यपाल डेका से रक्तवीर ऋषि ने की सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज रक्तवीर ऋषि अग्रवाल ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को रक्तदान के क्षेत्र में किए जा रहे अपने सेवाभावी कार्यों की जानकारी दी। ऋषि अग्रवाल ने बताया कि वे नियमित रूप से जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत बचत से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ष गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्होंने 54वीं बार रक्तदान किया। राज्यपाल डेका ने ऋषि के सेवा कार्यों की



सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता और रक्तदान के माध्यम से मानव जीवन की रक्षा करना अत्यंत पुनीत कार्य है। उनका यह सेवाभाव समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि रक्तदान जैसा निःस्वार्थ कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई उम्मीद देता है। ऐसे सेवाभावी लोग समाज की असली ताकत हैं, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ऋषि अग्रवाल को उनके सेवा कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं और भविष्य में भी इसी तरह मानव सेवा में लगे रहने का आशीर्वाद दिया।

शिक्षकों के 10 दिन के अर्जित अवकाश की मांग को लेकर फेडरेशन ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को मिलने वाले 10 दिन के अर्जित अवकाश नियम को लागू किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला सूरजपुर के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवकाश प्रावधान को लागू किए जाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक अथवा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अर्जित अवकाश का प्रावधान किया गया है, जो अन्य जिलों में लागू है। मगर सूरजपुर जिले में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा अन्य जिलों में लागू नियम के प्रमाण के साथ ज्ञापन सौंपकर इसे लागू करने की मांग की है। फेडरेशन की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने जल्द ही इस हेतु आदेश जारी किए जाने का फेडरेशन को आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शशिभूषण दुबे, जिला महामंत्री देवेंद्र पांडेय, मीडिया प्रभारी बोस प्रताप सिंह, सूरजपुर ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, अमोल सिंह, कोषाध्यक्ष बनारसी सिंह, प्रकाश सोलंकी, राम सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित थे।

हार के बाद भी जारी है समीक्षा, बूथ से मंडल तक संगठन मजबूत कर रही कांग्रेस - टीएस सिंहदेव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को निराशाजनक और एक तरह से अप्रत्याशित बताया है। जशपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को विश्वास था कि राज्य में दोबारा पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। उन्होंने बताया कि नतीजे आने के दिन से ही हार के कारणों पर आत्ममंथन शुरू हो गया था। सिंहदेव ने कहा कि चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, यह अलग विषय था, लेकिन सरकार बनने को लेकर भरोसा और विश्वास था। उनके मुताबिक, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के भीतर उन कारणों को समझने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनकी वजह से ऐसे परिणाम सामने आए।

संभाग में 14 से 0 पर पहुंची कांग्रेस

संभाग में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक चुनाव में पार्टी सभी 14 सीटें जीतती है और अगले चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुलता। सिंहदेव ने सवाल उठाया कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या रही। उनके अनुसार, इसी बिंदु से संगठन और चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा



का काम आगे बढ़ा।

संगठन को मजबूत करने पर जोर

कांग्रेस नेता ने बताया कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक वर्ष से अधिक समय से काम चल रहा है। इसमें मतदान केंद्र और ब्लॉक स्तर पर संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे में 'मंडल' नाम से नई इकाई स्थापित करने का भी उल्लेख किया। सिंहदेव के बयान में चुनावी परिणामों की समीक्षा के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर रहा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने की उम्मीद पूरी नहीं होने के बाद से पार्टी कारणों पर विचार कर रही है। बूथ और ब्लॉक स्तर की मजबूती तथा मंडल इकाई का गठन इसी संगठनात्मक काम का हिस्सा है। उनके मुताबिक, हार के बाद शुरू हुआ आत्ममंथन केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहा। सवाल यह भी रहा कि जिस संभाग में कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, वहां अगले चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं मिली। जशपुर में दिए बयान में सिंहदेव ने किसी एक कारण को हार की वजह नहीं बताया। उन्होंने परिणामों को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए समीक्षा और संगठन को मजबूत करने की जारी प्रक्रिया की जानकारी दी। उनका जोर मतदान केंद्र से लेकर ब्लॉक और मंडल स्तर तक पार्टी के ढांचे को सुदृढ़ करने पर रहा।

चिंतन

देश की राजनीति में रोकें विदेशियों का दखल

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना और सवाल उठाना विपक्ष और नेता विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में विदेशी नेताओं को देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने की छूट नहीं दी जा सकती। राजनीतिक विरोध और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। हैदराबाद में कांग्रेस के 'भारत समिट 2026' के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक की ओर से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया जाना इसी सीमा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 14 नवंबर को आयोजित सम्मेलन में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव ने मंच से यह नारा लगाया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्कुराते और तालियां बजाते नजर आए। सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति के मुद्दों पर विदेशी नेताओं से इस तरह नारेबाजी कराना उचित है? कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है। संसद से लेकर सड़क तक उसे सरकार से सवाल पूछने और जनता के बीच अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई विदेशी राजनीतिक नेता भारतीय धरती पर किसी दल के राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनकर सरकार विरोधी नारा लगाता है तो मामला केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता। इससे देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन मिलने की आशंका पैदा होती है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं से ऐसे अवसरों पर अधिक जिम्मेदारी और संयम की अपेक्षा की जाती है। कांग्रेस ने सम्मेलन का बचाव करते हुए इसे दुनिया भर के प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों के बीच संवाद का मंच बताया है। लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन विचारों का आदान-प्रदान और किसी देश की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में प्रत्यक्ष भागीदारी अलग-अलग विषय हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा और केंद्र सरकार ने इस घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विदेशी नेता की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस विदेशी नेताओं को मंच देकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है। यहां सरकारें बनती और बदलती हैं तो जनता के मत से, न कि किसी विदेशी राजनीतिक संगठन की राय या समर्थन से। इसलिए राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि सत्ता की लड़ाई में राष्ट्रीय हित और देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जा सकता। आज किसी विदेशी नेता को एक दल के मंच से सरकार विरोधी नारा लगाने की छूट दी जाती है तो कल दूसरे दल के मंच से कोई विदेशी भारत की संस्थाओं और नीतियों पर अनुचित टिप्पणी कर सकता है। ऐसी परंपरा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए कतई ठीक नहीं होगी। विदेशी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संवाद का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारत की घरेलू राजनीति में बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, मगर यह विरोध भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में ही होना चाहिए। देशहित और राजनीतिक हित के बीच टकराव की स्थिति में प्राथमिकता हमेशा देशहित को मिलनी चाहिए।



आर्थिकी

डॉ .जयंतीलाल भंडारी

अब चीन पर निर्भरता घटाना जरूरी

निश्चित रूप से इस समय एक ओर सीमा पर चीन की नई हलचल बढ़ने से सीमा चुनौती बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर चीन से होने वाले आयात में अभूतपूर्व और चिंताजनक उछाल भारत के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में चीन से भारत का आयात लगभग 47 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तमाम सरकारी कोशिशों, मेक इन इंडिया अभियानों और आत्मनिर्भर भारत के नारों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की कई आधारभूत जरूरतें आज भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गहराई से टिकी हुई हैं। चीन से बढ़ता व्यापार असंतुलन केवल एक साधारण आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की औद्योगिक स्वायत्तता, तकनीकी सुरक्षा और दीर्घकालिक राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने चीन द्वारा लगाए गए शुल्क और विभिन्न प्रतिबंधों को भारतीय निर्यात के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेनेरिक दवाओं और कृषि उत्पादों जैसी भारी संभावनाओं के बावजूद, चीन के गैर-शुल्क और पादप स्वच्छता संबंधी प्रतिबंधों के कारण भारतीय उत्पादों को चीनी बाजार में उचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार इस गंभीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर प्रमुखता से उठा रही है। स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लगभग 52.5 अरब डॉलर से बढ़कर यह व्यापार घाटा अब 112 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। चीन से आयात में तीव्र वृद्धि इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि हमारे विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की चीन पर निर्भरता कम होने के बजाय और अधिक गहरी और जटिल होती जा रही है। यद्यपि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' और पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजनाओं के बल पर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तृत हुआ है, लेकिन हमारे कारखानों का कच्चा माल, पुर्जे और मध्यवर्ती वस्तुएं (इंटरमीडिएट गुड्स) अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से ही आयात होती हैं। ऐसे में एक विरोधाभासी स्थिति यह बन रही है कि जैसे-जैसे भारत में अंतिम उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन और असेंबलिंग बढ़ती है, चीन से कच्चे माल और पुर्जों का आयात स्वतः ही अनुपातिक रूप से और अधिक बढ़ जाता है। इस विकट और चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और रणनीतिक राहत देने वाला तथ्य यह है कि प्रकृति ने भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में प्रचुरता बख्शी है। वैश्विक खनिज आंकड़ों (यूएसजीएस) के अनुसार, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' (दुर्लभ मृदा तत्व) का भंडार है, जो कुल वैश्विक भंडारों का लगभग 6 से 7.6 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के तटीय राज्यों-विशेषकर केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटीय क्षेत्रों-में मोनाजाइट रेत के रूप में यह खनिज खजाना प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हमारे



पास प्राकृतिक रूप से कच्चे अयस्क (रॉ ओर्स) का विशाल भंडार है, लेकिन इसके खनन, जटिल रिफाइनिंग, पृथक्करण (सेपरेशन) और उच्च-स्तरीय चुंबक (मैग्नेट) निर्माण के लिए आवश्यक 'मिडस्ट्रीम' और 'डाउनस्ट्रीम' औद्योगिक क्षमताओं का देश में भारी अभाव है। आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), विंड टर्बाइन, और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों में उपयोग होने वाले परमानेंट मैग्नेट के लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। चूंकि चीन ने इन रणनीतिक खनिजों के प्रसंस्करण और निर्यात पर कड़े नियंत्रण, प्रतिबंध व कोटे लगा रखे हैं, इसलिए भारत को अपने ही घर में मौजूद इस अपार संपदा का सामरिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेयर अर्थ के अलावा भी भारत के पास ऐसी कई आंतरिक अनुकूलताएं और सामर्थ्य मौजूद हैं, जिनके बल पर वह चीन पर अपनी इस अवांछित निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर सकता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और कुशल तकनीकी इंजीनियरों व युवाओं का सबसे बड़ा समूह है। यदि स्थानीय स्तर पर आरएंडडी (शोध और विकास) और डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए, तो हम चीन के उत्पादों के उत्कृष्ट और सस्ते विकल्प अपने देश में ही तैयार कर सकते हैं। भारत को दुनिया की 'फार्मेसी' कहा जाता है, हालांकि जीवनरक्षक दवाओं और एंटीबायोटिक्स के लिए उपयोग होने वाले लगभग 70 प्रतिशत एपीआई (सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक) के लिए हम आज भी चीन पर निर्भर हैं। देश में बल्क ड्रग पार्कों और केमीकल क्लस्टर्स के त्वरित विकास से इस निर्भरता को तेजी से तोड़ा जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यदि तय समयसीमा और मिशन मोड में धरातल पर उतर जाएं, तो कंपोनेंट स्तर पर आत्मनिर्भरता हासिल करना असंभव नहीं होगा। ऐसे में हमें इस बात को समझना होगा कि केवल सतही उपायों या दंडात्मक सीमा शुल्क लगाने से चीन से व्यापार असंतुलन की समस्या हल नहीं होने वाली है। इसके लिए एक दीर्घकालिक, समग्र और आक्रामक कार्ययोजना पर काम करना होगा। हमें केवल अंतिम उत्पादों की असेंबलिंग तक सीमित न रहकर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), डिस्प्ले पैनल, एडवांस्ड सेंसर, कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर चिप्स का मूल विनिर्माण देश के भीतर ही करना होगा। जब तक देश में कंपोनेंट इकोसिस्टम विकसित नहीं होगा, आयात कम नहीं हो सकता। पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर हमें घरेलू खनन को तत्काल गति देनी होगी। क्रिटिकल मिनरल्स और उच्च-तकनीकी इनपुट के मामले में चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के साथ 'मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप' और द्विपक्षीय समझौतों को और अधिक मजबूत करना होगा, ताकि सुरक्षित और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके। भारतीय बाजारों में घटिया, कम कीमत वाले और डंप किए जाने वाले चीनी सामान के प्रवेश को रोकने के लिए मानक ब्यूरो के माध्यम से कड़े गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए जाने चाहिए। निसंदेह चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक स्पष्ट और गंभीर चेतावनी है। जब देश के उद्यमी, वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और करोड़ों जागरूक उपभोक्ता स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे, तभी भारत चीन पर अपनी अनावश्यक और जोखिम भरी निर्भरता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

प्रेस दिवस विशेष

राजेश जैन



खबर से बड़ा हुआ बाजार

लोकतंत्र को मीडिया चाहिए या सिर्फ खबरों का कारोबार? यह सवाल आज इसलिए अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि खबरों की दुनिया पहले से कहीं बड़ी हो गई है, लेकिन सच तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। सुबह अखबार खोलिए, टीवी चलाइए या मोबाइल पर सोशल मीडिया देखिए; हर ओर खबरें, घटनाओं के वीडियो, विशेषज्ञों की राय, बहसें और हर मुद्दे पर तत्काल प्रतिक्रियाएं हैं। सूचना की इस बाढ़ में कमी सिर्फ एक चीज की महसूस होती है- ठहरकर सच की पड़ताल करने की। पत्रकारिता का संकट यह नहीं है कि लोग खबरें पढ़ या देख नहीं रहे। असली संकट यह है कि खबरों की बहुतायत के बीच पाठक यह तय नहीं कर पा रहा कि किस पर भरोसा करें। एक ही घटना पर अलग-अलग दावे, आधे-अधूरे तथ्य, पुराने वीडियो को नई घटना बताकर प्रसारित करना और बिना पुष्टि के वायरल होती सूचनाएं इस भरोसे को लगातार कमजोर कर रही हैं। ऐसे में पत्रकारिता की भूमिका केवल सूचना पहुंचाने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे सूचना और सत्य, दावे और तथ्य तथा प्रचार और खबर के बीच का फर्क भी स्पष्ट करना होगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

इसी दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना भी था। यानी प्रेस की आजादी और उसकी जिम्मेदारी को शुरू से ही एक-दूसरे का पूरक माना गया। आज, जब मीडिया का स्वरूप, पहुंच और प्रभाव तेजी से बदल रहे हैं, इस मूल भावना को नए सिरे से समझने की जरूरत है। एक समय खबर पाठक तक पहुंचने के लिए अखबार के अगले संस्करण या रेडियो-टीवी बुलेटिन का इंतजार करती थी। अब घटना होते ही उसका वीडियो और उससे जुड़ा दावा कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। इस बदलाव ने सूचना के प्रसार को तेज और व्यापक बनाया है। आपदा, दुर्घटना, स्थानीय समस्या या प्रशासनिक लापरवाही की जानकारी अब किसी बड़े मीडिया संस्थान की मोहताज नहीं रही। आम नागरिक भी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सार्वजनिक कर सकते हैं। सूचना के इस लोकतंत्रीकरण ने खबरों की दुनिया में नए रास्ते खोले हैं। लेकिन सूचना का प्रसार आसान होने के साथ उसकी विश्वसनीयता की चुनौती भी बढ़ी है। आज पत्रकारिता की कसौटी केवल सबसे पहले खबर देने की नहीं, बल्कि उसकी पुष्टि कर सही संदर्भ के साथ पाठक तक पहुंचाने की है। पत्रकारिता की मूल भूमिका सत्ता से सवाल पूछना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और व्यवस्था को जवाबदेह बनाना रही है, लेकिन आज टेलीविजन समाचारों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, तीखी बहसों और सनसनी के बीच उलझा दिखाई देता है। लोकतंत्र में असहमति और विचारों का टकराव जरूरी है। समस्या तब पैदा होती है, जब बहस का उद्देश्य मुद्दे को समझना नहीं, बल्कि दर्शक को बांधे रखना बन जाता है। स्टूडियो में ऊंची आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन गांव में पानी की समस्या, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद या मजदूरों की मजदूरी जैसे सवाल उतनी जगह नहीं पाते। खबर का महत्व उसके जनहित से तय होना चाहिए, न कि उससे पैदा होने वाली उत्तेजना से। टीआरपी और विज्ञापन आधारित मॉडल ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। टेलीविजन रेटिंग दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों की लोकप्रियता मापने का माध्यम है। इसका सीधा संबंध विज्ञापन से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खबरें लिखने, संपादित करने, अनुवाद करने और प्रसारित करने के तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है। इससे काम की गति बढ़ सकती है और सीमित संसाधनों वाले संस्थानों को भी मदद मिल सकती है। लेतकनीक पत्रकार की जिम्मेदारी कम नहीं करती। एआई से तैयार सामग्री में गलत तथ्य, काल्पनिक संदर्भ और भ्रामक निष्कर्ष हो सकते हैं। डीपफेक वीडियो और कृत्रिम तस्वीरें किसी व्यक्ति के बयान या घटना को लेकर भ्रम पैदा कर सकती हैं। ऐसे दौर में पत्रकार की असली उपयोगिता उसकी मानवीय समझ, स्रोतों तक पहुंच, सवाल पूछने की क्षमता और तथ्यों की पड़ताल में होगी। तकनीक खबर तैयार करने में सहायक हो सकती है, लेकिन उसकी सत्यता और जवाबदेही किसी एल्गोरिदम पर नहीं छोड़ी जा सकती। खासकर जब किसी खबर में एआई से तैयार तस्वीर, वीडियो या सामग्री का इस्तेमाल हुआ हो और उससे उसके अर्थ या विश्वसनीयता पर असर पड़ता हो, तो पाठक को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, पत्रकारिता का मूल आधार वही रहेगा- तथ्य, सत्यापन और जवाबदेही।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ज्ञान



सर्व सामर्थ्य होते हुए भी अहंशून्य होकर स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता है। भगवान के परम भक्त बालिपुत्र अंगद ने रावण की सभा में अपना एक पैर रोपकर अपने मुष्टिप्रहार से रावण के दसों मुकुटों को सिर से गिरा दिया था, वहीं चार मुकुटों को बीच में उछालकर भगवान के पास भेज दिया था। लंका से

अनुकरण अच्छा, अंधानुकरण नहीं



एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों में बड़ी मैत्री थी। जहां जाते साथ-साथ जाते। एक बार दोनों एक धनी व्यक्ति के साथ उसकी ससुराल गए। किसी धनी व्यक्ति के साथ रहने का यह पहला अवसर था, सो वे अपने धनी मित्र की प्रत्येक गतिविधि ध्यान से देखते रहे। गरमियों के दिन थे। रात में उक्त युवक के लिए



संकलित

दर्शन

लौटकर आए अंगद से जब भगवान श्रीराम ने पूछा कि तुमने ये मुकुट कहां और कैसे प्राप्त किए, तब अंगद ने धर्म और ईश्वर से विमुख व्यक्ति की तात्विक व्याख्या की है। अंगद विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु! ये चार मुकुट नहीं, राजनीति के चार पद हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। रावण आपसे और धर्म से विमुख हो चुका है, इसलिए राजनीति के चारों चरणों (साम, दाम, दंड और भेद) का दुरुपयोग कर रहा था, इस कारण मुकुट के रूप में ये चारों उसको छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। रावण ने शेष छह मुकुट जो सिर पर धारण कर रखे हैं, वे साधक के जीवन में रहने वाली षड्संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान) हैं। चूंकि रावण उनका भी दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए ये षड्संपत्ति न रहकर विकार बनकर रावण के सिर पर शासन कर रहे हैं, जो उसके विनाश के कारण बनेंगे। मेरे प्रभु! गुण तो केवल वे ही हैं, जिन्हें आपने स्वीकारा है। शेष सब अवगुण ही हैं। गुणों का योग जब तक भगवान से नहीं होगा, तब तक व्यक्ति उसका उपयोग और कहां करेगा?



संकलित

प्रेरणा

शयन का व्यवस्था खुल स्थान पर का गइ। पयाप्त शातलता बना रह इसक लए वहाँ चारों तरफ जल छिड़का गया और रात को ओढ़ने के लिए बहुत ही हलकी मखमली चादर दी गई। अन्य दोनों युवकों ने इतना ही जाना कि इस तरह का रहन-सहन बड़प्पन की बात है। कुछ दिन बाद उन्हें भी अपनी-अपनी ससुराल जाने का अवसर मिला पर वे दिन गरमी के न होकर शीत के थे। नकल तो नकल ही है। दोनों ने अपना बड़प्पन जताने के लिए बिस्तर खुले आकाश के नीचे लगवाया, लोगों के लाख मना करने पर भी उन्होंने बिस्तर के आस-पास पानी भी छिड़कवाया और ओढ़ने के लिए कुल एक-एक चादर वह भी हलकी ली। रात को पाला पड़ गया सो दोनों को निमोनियाँ हो गया । चिकित्सा कराई गई तब कठिनाई से जान बची। इतनी कथा सुनाने के बाद गुरुजी ने शिष्य को समझाया–' तात ! उचित और अनुचित का विचार किए बिना जो औरों का अनुकरण करता है वह मूर्ख ऐसे ही संकट में पड़ता है जैसे वह दोनों युवक।'!

अंतर्मन



आज की पाती

उचित खानपान व जीवनशैली रोकेगी डायबिटीज

अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज रोकथाम दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज हमारी गलतियों के कारण बहुत सी जानलेवा बीमारियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन्हीं में से एक बीमारी है डायबिटीज जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। दुनियाभर में बढ़ते मधुमेह के आंकड़ों पर चिंता करते हुए इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन ने डायबिटीज रोकथाम दिवस मनाने का फैसला वर्ष 1991 में किया था। डायबिटीज का कहर खानपान और जीवनशैली की तरफ ध्यान देकर रोका जा सकता है। इस बीमारी के शिकार युवा भी हो रहे हैं। यह बीमारी हमारे देश में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीमारी का मुख्य कारण गलत खानपान और जीवनशैली भी है। इसलिए जीवनशैली को दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। - डा. प्रशांत शुक्ला, बावल, भिवानी

ट्रेंड

हार्दिक शुभकामनाएं



छठ महापर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति की आराधना को समर्पित यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई चेतना और ऊर्जा का संचार करे, तथा समाज में आपसी सद्भाव और एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाए। भगवान सूर्य की कृपा से सभी का जीवन प्रकाशमय हो।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

छठ पूजा पर्व



विश्व के इतिहास में छठ पूजा जैसा कोई दूसरा त्योहार मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जहां एक सामान्य गृहस्थ, बिना किसी रीति-रिवाज, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी की सहायता के, सीधे भगवान सूर्य से संवाद करता हुआ दिखाई देता है।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी

लक्ष्य का बेहतरीन खेल



भारतीय बैडमिंटन के लिए क्या शानदार दौर है! लक्ष्य सेन ने बेहतरीन खेल दिखाया, रैलियों में अपना दबदबा बनाया और शानदार स्मैश के दम पर कुमामोटो मास्टर्स जापान 2026 में लगातार अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 खिताब जीत लिया।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

सफलता की विडंबना



सफलता की एक बड़ी विडंबना यह है कि आप जितना ऊपर पहुंचते हैं, आपके लिए सच सुनना उतना ही मुश्किल हो जाता है। खेल की दुनिया में मैं भाग्यशाली था कि मुझे ऐसे कोच मिले जो मुझे साफ-साफ बता सकते थे कि मैं कहां गलती कर रहा हूँ।

- अभिनव बिंद्रा, ओलंपियन



करंट अफेयर

हैकाथॉन में भाग लेने वाले सीमाओं से परे सोचें: जोशी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को सिंगापुर-भारत हैकाथॉन 2026 के 120 प्रतिभागियों से नवोन्मेषी समाधान तलाशते समय सीमाओं से परे सोचने का आह्वान किया। जोशी ने सिंगापुर में आयोजित तीन दिवसीय हैकाथॉन की शुरुआत करते हुए कहा, 'सीमाओं से परे सोचें। अपने समाधान को किसी एक शिक्षण संस्थान के परिसर या देश तक सीमित न रखें।' उन्होंने दोनों देशों के संस्थानों द्वारा आयोजित इस हैकाथॉन के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से कहा, 'मानवता के लिए नवोन्मेष करें। मिलकर काम करें और दूसरे देश से आए अपने साथियों के विचारों को सुनें।' जोशी ने कहा कि भारत ने जब भी कुछ विकसित किया है, मानवता के हित में किया है। उन्होंने इस संदर्भ में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा लगभग 100 देश को टीके भेजे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने 36 घंटे तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे 60 विद्यार्थियों से कहा कि सिंगापुर और भारत नवोन्मेष के लिए परीक्षण केंद्र, संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र और शिक्षकों के आदान-प्रदान की दिशा में काम कर रहे हैं तथा दोनों देश ऐसे भविष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं, जहां भारत में प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र सिंगापुर में भी मान्य होगा।



ऑफ बीट

अंडाशय के कैंसर में मददगार हो सकती है खून की जांच

अंडाशय का सबसे आम प्रकार का कैंसर तेजी से फैलता है, जिसे 'हाई-ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर' कहा जाता है और इसकी शुरुआत अक्सर फैलोपियन ट्यूब (अंडवाहिनी) में होती है। ये वे नलिकाएं हैं, जो अंडाशय से अंडों को गर्भाशय तक पहुंचाती हैं। इस कैंसर की शुरुआती कोशिकीय गड़बड़ियां इतनी सूक्ष्म हो सकती हैं कि आमतौर पर सर्जरी के बाद जब विशेषज्ञ फैलोपियन ट्यूब के ऊतक की माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं, तभी उनका पता चल पाता है। लेकिन अब एक नए अध्ययन में संकेत मिले हैं कि इन शुरुआती बदलावों की पहचान खून की जांच से भी संभव हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पहले से सुरक्षित रखे गए रक्त के नमूनों में 'टीयू-स्ट्रोमा' नाम के एक अणु की तलाश की। उन्हें ऐसे लोगों के खून में इस अणु का स्तर अधिक मिला, जिनमें कैंसर शुरुआती अवस्था में था और आसपास के ऊतकों में फैलना शुरू हो गया था। इस अणु का स्तर उन लोगों में भी अधिक पाया गया, जिनकी फैलोपियन ट्यूब की अंदरूनी परत में असामान्य कोशिकाओं का एक बेहद छोटा समूह मौजूद था। ये कोशिकाएं अभी उसी परत तक सीमित थीं और आसपास के ऊतकों में नहीं फैली थीं। इस स्थिति को 'सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथीलियल कार्सिनोमा' यानी 'स्टिक' कहा जाता है।



खबर संक्षेप

कुए की मिट्टी गिरने से 4 मजदूरों की मौत

सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी और चट्टानों का



मलबा गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई। सोलापुर के जिलाधिकारी एस. कार्तिकेयन ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे पंढरपुर तालुका के आंबे गांव में हुई। वहां एक खेत में जेसीबी मशीन की मदद से 50 फुट गहरा कुआं खोदा जा रहा था।

शिमला में कार खाई में गिरी, 3 की मौत

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सोमवार सुबह एक कार के सड़क से फिसलकर गहरी



खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा रामपुर उपमंडल में रामपुर-गौरा संपर्क मार्ग पर सुबह लगभग तीन बजे हुआ। चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार 700-800 फुट गहरी खाई में जा गिरी।

कर्नाटक सीएम ने आवास का नाम 'गंगा' रखा

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने यहां कुमार कृपा अतिथि गृह के पुराने भवन का नाम बदलकर 'गंगा'



रखने के साथ ही इसे सीएम डीके शिवकुमार का आधिकारिक आवास घोषित कर दिया।

एसआईआर को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच फिर विवाद तेज

ऑनलाइन पोर्टल और वोटर लिस्ट में बदलाव पर भी किए सवाल

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल, ईसी से मांगे 48 सवालों के जवाब

याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे? इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला किसने लिया था?

सीईसी के एकतरफा फैसले लेने पर उठाए सवाल



फॉर्म 6 में बदलाव और राज्यों में हटाए गए नामों का ब्योरा मांगा

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीख या बैठकों का ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है। इसके मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।

तीन अधिकारियों से मांगा जवाब

अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने मांग की है कि फरवरी 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म-6 या अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर कब-कब लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया।

8.5 लाख किताबें शिफ्ट करने की जल्दबाजी क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। मामला दिल्ली के 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी पुस्तकालय की विरासत को बचाने के लिए बिना किसी ठोस योजना के काम करते दिख रहे हैं। आप इस काम को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं।

सीजेआई के साथ वकील ने की बदसलूकी

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया। वकील ने सुनवाई के दौरान सीजेआई पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं। घटना के बाद अदालत की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई।

बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को जमानत

बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था।

यमुना को प्रदूषण करने वालों पर लगेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। यह नदी के किनारे बसे कस्बों और शहरों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीसीबी से मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने को कहा गया है, जिसे राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल सकते हैं।

अजित पवार को याद कर भावुक हुए शाह



अजीत पवार की मूर्ति का अनावरण करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

आंखें बंद करूं तो दिखते हैं दादा, उनका जाना बड़ी क्षति

एजेंसी ▶▶ पुणे

महाराष्ट्र के पुणे में दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, और उनके नाम पर रखी गई जिला परिषद भवन की प्रवेश-द्वार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दादा का अचानक और असामयिक निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उनका असामयिक निधन को न केवल महाराष्ट्र, बल्कि विशेष रूप से पुणे, बारामती, पिंपरी और चिंचवड़ क्षेत्रों के लिए अपूरणीय क्षति है। दादा का व्यक्तित्व इतना जीवंत और सकारात्मक था कि आज भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे दादा अपने ठीक सामने खड़े दिखाई देते हैं।

दादा की मौत की रिपोर्ट सार्वजनिक हो: सीएम

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजित पवार विमान हादसे की जांच में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में उठ रहे सवालों और आशंकाओं का जवाब मिल सके। हादसे की जांच महाराष्ट्र सीआईडी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाला विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) अलग-अलग कर रहे हैं। 8 से 10 महीने बीत चुके हैं और बड़े स्तर पर जांच चल रही है। अलग-अलग देशों की टीमें और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें मदद कर रही हैं।

'भारत टैक्सी' सेवा का शुभारंभ किया

अमित शाह ने पुणे में एनएचईसी मल्टी स्टेट सहकारी संस्था का भूमिपूजन किया। 110 एकड़ में फैली यह इकाई चीनी मिल मशीनरी, सीबीजी और डेयरी संयंत्र बनाएगी, जिससे किसानों को गन्ने और दूध के हर उत्पाद का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र भारत को उत्पादन से लेकर उद्योग तक आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही, पुणे में 'भारत टैक्सी' सेवा का शुभारंभ भी किया और सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। देश के अनेक शहरों में शुरू हो चुकी 'भारत टैक्सी' चालकों को सम्मान, स्वाभिमान के साथ यात्रियों को भरोसेमंद व सुरक्षित आवागमन दे रही है।

बंगाल में रतन शेख की मौत पर विवाद तेज

फिलिबेक के बयान पर सियासी घमासान

21 करोड़ कीमत का घोड़ा 'गोल्डन किंग'

भाजपा ने कहा- अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई जारी रहेगी

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस मुठभेड़ में रतन शेख की मौत के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। रतन शेख एक पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाने का मुख्य आरोपी था। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है, जबकि विपक्षी दलों ने मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार अदालतों के पास होना चाहिए। सोमवार को बीरभूम के पुलिस अधीक्षक ने दोहराया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में रतन शेख के दो सहयोगियों रमेश लोहार और नूर हुसैन शेख को भी गिरफ्तार किया गया है। रतन शेख के खिलाफ 36 मामले दर्ज थे, जबकि उसके सहयोगी रमेश लोहार के खिलाफ 17 से 18 मामले दर्ज थे। इनमें लूटपाट और अवैध हथियारों से जुड़े मामले शामिल हैं।



सीएम सुवेंदु

भाजपा बोली- भारत विरोधी ताकतों को साथ ला रहे राहुल

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भाजपा ने सोमवार को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के जरिए कथित भारत विरोधी ताकतों को मंच दिया और देश को बदनाम करने तथा अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 14 नवंबर को हुए भारत समिट को 'एंटी इंडिया समिट' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को एक साथ लाने में जुटे हैं। राहुल गांधी ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ते, जहां से भारत को बदनाम करने, अव्यवस्था फैलाने और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा सके। बता दें, यूरोपीय सोशलिस्ट्स पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था। भाटिया ने कहा कि उन्हें कांग्रेस ने जानबूझकर यह अवसर उपलब्ध करवाया था।



गौरव भाटिया



अजमेर। गुजरात के सूरत से पहुंचा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा गोल्डन किंग मेले के सबसे चर्चित आकर्षणों में शामिल है। इसके मालिक के मुताबिक इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए है। पांच साल के इस घोड़े का रंग क्रिमिनो है। मालिक का दावा है कि देश में इस रंग का मारवाड़ी नस्ल का यह इकलौता घोड़ा है। इसकी ऊंचाई 65 इंच है। अब तक इससे छह बच्चे हो चुके हैं। इसकी ब्रीडिंग फीस करीब डेढ़ लाख रुपए ली जाती है। मालिक इसे खरीद-बिक्री के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पुष्कर मेले में दिखाने के लिए लाए हैं। मेले में 800 किलो वजन का भैंसा 'छोटा सुल्तान' भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गायों से लेकर यूरोप की शेटलैंड पोनी तक इस बार पुष्कर मेले में पशुओं की अनोखी दुनिया देखने को मिल रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की पसंदीदा पुंगनूर गाय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं रतीमा उरॉव (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी-राजू एक्का, शहर/गाँव-पालीडीह, पत्थलगांव, तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम रतीमा उरॉव (पुराना नाम) से बदल कर प्रतिमा एक्का (नया नाम) रख लिया है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र० ०/ब-121/2026-27

प्रस्तावित नक्शा का अंतिम ईश्तहार प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा०प्र०क्र० ०/ब-121/2026-27 सुभाष राय. प्रति छ.ग. शासन में ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नबर 214/5 रकबा 0.560 हे. भूमि का नक्शा सुधार कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मंगाया गया। राजस्व निरीक्षक, अम्बिकापुर-4 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौके पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खसरा नंबर 272/38 बनारस रोड से लगी भूमि है जिसका नया खसरा नंबर 211 एवं 213 बना है आवेदक के भूमि खसरा नंबर 214/5 के सामने में खसरा नंबर 213 निर्मित हुआ है जो खसरा नंबर 272/38 का भाग है जो त्रुटिवश आवेदक के भूमि खसरा नंबर 214/5 के सामने बना है। जिसके कारण आवेदक के भूमि का नक्शा में त्रुटि हो रहा है। खसरा नंबर 213 को खसरा नंबर 214/5 के सामने से स्थान परिवर्तन करके जैसा कि पुराने नक्शा में 272/38 नया खसरा नंबर 211 एवं 213 जो बनारस रोड से लगकर भूमि है उसमें अंकित किया जाना उचित होगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा सुधार कर प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त नक्शा सुधार में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 04/12/2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 16/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र० 202611021700006/ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका छाया दास पत्ति स्व० खगेन्द्र, व अन्य 02, निवासी सांई कॉलेज पारा, ग्राम डिगमा, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चठिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 385/2 रकबा 0.380 हे0 में से 0.200 हे0 भूमि मकान बनाने एवं निजी कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद साहू आ० स्व० बेनी माधव साहू, निवासी ग्राम मणीपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) को रू0 10,00,000/- (दस लाख रुपए) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09/12/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 11/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० /अ-20(3)/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक सरिता अग्रवाल पति अभय अगवाल, निवासी बंगला नंबर-3-155 स्वर्ण भूमि विधानसभा रोड़, आमासिवनी, रायपुर जिला रायपुर छ०ग० द्वारा मुख्तार आम रवि कुमार अग्रवाल आ. गुलाब अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-3 मोहल्ला- देवीगंज रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2917/19, 2918/4, 2918/15 रकबा 0. 016, 0.016, 0.016 हे० भूमि को अनावेदक/केता रवि कुमार अग्रवाल आ. गुलाब अग्रवाल निवासी अग्रसेन वार्ड, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सूरजपुर, छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टनेंस खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27.11.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 13.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं कैलाश (KAILASH) आत्मज हिरालाल (HEERA Lal) उम्र 41 वर्ष जाति गोड़ निवासी ग्राम रामेश्वरम मदनपुर थाना व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं अपनी पुत्री कु. शिशु (KU. SHISHU) यह पुराना नाम कु. शिशु को बदलकर नया नाम शीला (SHILA) करवाना चाहता हूं जो की मेरे पुत्री का कक्षा पांचवी के अंक सूची में भी दर्ज है मेरे पुत्री के पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः यदि मैं अपना पुत्री का नाम बदलवाकर कोई भी गैर कानूनी काम करता हूं तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा इस हेतु मेरे द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। शपथ करता कैलाश निवासी ग्राम रामेश्वरम, मदनपुर थाना वह तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।

आवेदक
कैलाश(KAILASH)
पिताः- हिरालाल (HEERA LAL)
निवासी रामेश्वरम मदनपुर सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ.ग.) - 497333

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक ताराचन्द गुप्ता आ० स्व. सोहर लाल गुप्ता, निवासी करजी, तहसील दरिमा, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला सदर रोड़, नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर-03 स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 1383/1 रकबा 0.01 1/4 एकड़ भूमि तथा निर्मित दुकान को अपने भाई अनावेदक राधेकृष्ण गुप्ता आ. स्व. सोहर लाल गुप्ता, निवासी सदर रोड़, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में दान करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17.11.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०- /ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुपमा जोशी पत्नी स्व० श्यामकृष्ण जोशी निवासी एम०जी०रोड होटल शैलगिरी के पास भगवानपुरकला वर्तमान निवासी सूर्यबिहार मोतीलाल नेहरूनगर भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भगवानपुरकला स्थित भूमि खसरा नंबर 217/2 रकबा 0.030 हे0 भूमि को अनावेदक अच्छेलाल यादव आ०स्व० रामवृक्ष यादव निवासी बी-केरा जरही कॉलोनी उर्जानगर थाना भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 के पास अंकन राशि रुपए 37,29,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 30.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांकः- 06/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०- /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका कांति जायसवाल आ०/पति प्रदीप कुमार अग्रवाल जाति निवासी राजपुर तहसील राजपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मणीपुर लखनपुर रोड़, शीट नम्बर 6 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4237/12 रकबा 0.02 3/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-25.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 10.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०- /ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ज्ञानेश जोशी आ०स्व० श्यामकृष्ण जोशी निवासी ए-4603, अकोलाडे सोसायटी मुंध्वारोड खराडी हयूंदाई शोरूम खराडी पूर्ण शहर पूर्ण महाराष्ट्र के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भगवानपुरकला स्थित भूमि खसरा नंबर 217/3 रकबा 0.050 हे0 भूमि को अनावेदक अच्छेलाल यादव आ०स्व० रामवृक्ष यादव निवासी बी-केरा जरही कॉलोनी उर्जानगर थाना भटगांव जिला सूरजपुर छ०ग० के पास अंकन राशि रुपए 62,15,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 30.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांकः- 06/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

वरिष्ठजनों का अनुभव और मार्गदर्शन समाज के लिए अनमोल धरोहर : विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कवर्धा। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कहा कि वरिष्ठजन समाज की अनमोल धरोहर हैं। उनका अनुभव, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और जीवनभर का अर्जित ज्ञान पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है। आज तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में वरिष्ठजनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उनके अनुभव और संस्कार समाज को संबल प्रदान करते हैं। उपमुख्यमंत्री शर्मा कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सातवें प्रादेशिक सम्मेलन-2026 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 'अनुभूति' पत्रिका का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है, लेकिन यह ऐसा आयोजन है, जहां वे कुछ देने नहीं, बल्कि वरिष्ठजनों से आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के लंबे अनुभव के बाद वरिष्ठजन परिवार और समाज के लिए उस ब्याज के समान हैं, जो मूल से भी अधिक प्रिय हो जाता है। उन्होंने कहा कि पहले लोग एक साथ बैठकर समय बिताते थे, लेकिन आज मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से सामाजिक मेलजोल कम हुआ है। तेजी से बदलते इस दौर में वरिष्ठजनों का अनुभव और संस्कार समाज को संबल प्रदान कर सकते हैं।

30 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा सियान सदन

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कवर्धा के वरिष्ठजनों की प्रेरणा और सुझाव पर शहर में सियान सदन का निर्माण प्रारंभ कराया गया है। इसके लिए लगभग 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सियान सदन का निर्माण उसी स्थान पर कराया जा रहा है, जिसे वरिष्ठजनों ने स्वयं इसके लिए उपयुक्त बताया था।



उन्होंने कहा कि सियान सदन वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय बिताने, आपस में मिलने-जुलने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का बेहतर केंद्र बनेगा। सियान सदन में वरिष्ठजन कैरम, शतरंज, अध्ययन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समय बिता सकेंगे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भविष्य में बैटरी चलित छोटे वाहन की व्यवस्था करने की योजना भी साझा की। इसके माध्यम से वरिष्ठजन फोन कर वाहन बुला सकेंगे और घर से सियान सदन आने-जाने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

वरिष्ठजनों की यादों में हमेशा जीवित रहता है बचपन

उपमुख्यमंत्री ने परिवार के भावनात्मक रिश्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि मां के लिए बेटा उम्र में कितना भी बड़ा हो जाए, वह हमेशा उसका छोटा बच्चा ही रहता है। उन्होंने वरिष्ठजनों से आग्रह किया कि बचपन की प्यारी यादों को संजोकर रखें, क्योंकि यही यादें जीवन में प्रसन्नता और आत्मिक सुकून देती हैं। उन्होंने सम्मेलन के कवर्धा में आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजकों को बधाई दी और वरिष्ठजनों को सियान सदन के निर्माण के बाद वहां भी इसी तरह सम्मेलन आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत कबीरधाम के अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, कॉन्फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश देवरस, प्रांतीय महासचिव धनेश सोलंकी, डॉ. अतुल जैन, शुभंकर विश्वास और लालचंद जैन, आदित्य श्रीवास्तव सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

मेहनत को मिली पूंजी, छोटे कारोबारियों के सपनों को उड़ान दे रही पीएम स्वनिधि : अरुण साव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में कहा कि ठेला-खोमचा वालों की मेहनत को पीएम स्वनिधि ने पूंजी का सहारा दिया है। कभी साहूकारों को ब्याज में जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी मजबूत बनें, एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा तभी प्रदेश और देश विकसित होगा। उन्होंने कार्यक्रम में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और



पोस्टर का विमोचन किया। कहा कि पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय में सुविधा होगी। हितग्राहियों को यूपीआई डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स वितरित किए और सफल पथ विक्रेताओं व उनके प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया।साव ने कहा कि पहले कारोबार के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था। कोरोना काल में आजीविका का गंभीर संकट आया। प्रधानमंत्री ने 2020 में पीएम स्वनिधि शुरू की। बिना गारंटी आसान ऋण से लाखों विक्रेताओं को कारोबार फिर खड़ा करने का अवसर मिला। योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने नियमित भुगतान कर अगले चरण का लाभ लेने, आमदनी बढ़ाने, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। डिजिटल लेन-देन और 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने को भी कहा।उन्होंने कहा कि बिलासपुर लगातार उपलब्धियां जोड़ रहा है। स्वच्छता में बिलासपुर को देश में दूसरा और बिल्हा को छोटे शहरों में पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया। पीएम स्वनिधि के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निकायों, बैंकर्स, अधिकारियों और हितग्राहियों को बधाई दी।

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता, पथ विक्रेता अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, योजना उन्हें संबल के साथ आत्मविश्वास और गौरव दे रही है। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि योजना आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है, वंचित पात्रों को जोड़ने और ऋण प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया। कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत ने निजी कर्ज की कठिनाइयों से राहत दिलाने में योजना की भूमिका बताई।

गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे अमित जोगी, पीएम और सीईसी पर बनाए वीडियो को लेकर दर्ज हुई एफआईआर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अमित जोगी रायपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल, हाल ही में अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के किरदारों को लेकर प्रस्तुति दी गई थी। वीडियो को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भाजपा नेता राजेश मूणत ने इस मामले में सिविल लाइन थाने पहुंचकर अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मूणत ने वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इस तरह की प्रस्तुति करना बेहद निंदनीय है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि राजनीति में सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। अपनी बात रखने का एक तरीका और मयार्दा होती है, लेकिन इस तरह के वीडियो के जरिए राजनीतिक विरोध जताना उचित नहीं है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस अमित जोगी से पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

मुख्यमंत्री से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की सौजन्य मुलाकात

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर रेवंत रेड्डी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुलाकात के दौरान तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट



बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी कार्यकताओं का ऐलान मानदेय नहीं बढ़ा तो आंदोलन तेज होगा, 29 नवंबर को मनाएंगी काला दिवस



रायपुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर अब आंदोलन के रास्ते पर उतरने जा रही हैं। मानदेय में बढ़ोतरी और नियमितीकरण सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तर पर तीन दिवसीय चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अलग-अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी है। आंदोलन के पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी समस्याओं और मांगों को सार्वजनिक रूप से उठाएंगी। इसके माध्यम से वे अपनी जिम्मेदारियों, कार्य परिस्थितियों और लंबे समय से लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगी।

स्वनिधि महोत्सव में अरुण साव ने हितग्राहियों के स्टॉल देखे, कुल्हड़ चाय-गुपचुप-फरा का लिया स्वाद



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में स्वनिधि महोत्सव में पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया, बिक्री और आमदनी के बारे में आत्मीयता से चर्चा की तथा कारोबार बढ़ाने के उनके प्रयासों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने स्टॉल्स के भ्रमण के दौरान अन्य अतिथियों के साथ कुल्हड़ में चाय, गुपचुप और फरा का स्वाद भी लिया।

'कुल्हड़ पर चौपाल' में महिला पथ विक्रेताओं से हुए रू-ब-रू, सुनी आत्मनिर्भरता की कहानियां

उपमुख्यमंत्री साव ने स्वनिधि महोत्सव में आयोजित 'कुल्हड़ पर चौपाल' में पीएम स्वनिधि योजना के महिला लाभार्थियों के साथ मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हुए आत्मीय संवाद किया। उन्होंने महिलाओं से उनके व्यवसाय, अनुभवों और पीएम स्वनिधि योजना से मिले लाभों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान महिला हितग्राही काफी उत्साहित नजर आईं। सहज और आत्मीय वातावरण में हुई इस चर्चा ने महोत्सव को खास बना दिया। कुल्हड़ के उपयोग के माध्यम से स्थानीय परंपरा को प्रोत्साहित करने और प्लास्टिक के विकल्प को अपनाने का संदेश भी दिया गया।

प्रदेश में कार्यरत आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का डीए 3% बढ़ा, 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद अधिकारियों को अब 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 29 अक्टूबर



2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की थी। अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत यह संशोधित दरें राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगी।सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से देने की स्वीकृति दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि से देय महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। यानी जुलाई से लेकर अब तक का एरियर्स भी अधिकारियों को नकद मिलेगा।

वेतन के आधार पर होगी गणना

आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल के तहत आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।भुगतान का नियमन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

किसे मिलेगा लाभ

इस आदेश का लाभ छत्तीसगढ़ कैडर में कार्यरत सभी आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अधिकारियों को हर माह वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

डीपीआई का कड़ा आदेश, लापरवाही बरतने वाले डीईओ का वेतन अगले आदेश तक रोका

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। ऑनलाइन अटेंडेंस में लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऐप का डेटा अपडेट नहीं करने पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा समेत 19 जिलों के डीईओ की नवंबर 2026 की सैलरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

बार-बार रिमाइंडर के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी के आदेश के अनुसार, 8 अक्टूबर को उन शिक्षकों-कर्मचारियों का डेटा गूगल शीट पर मांगा गया था, जो वीएसके ऐप से हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। 3 नवंबर को रिमाइंडर के बाद भी 17 जिलों ने डेटा नहीं भेजा। वहीं 16 अक्टूबर को ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी स्टाफ ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहा। 4 नवंबर की चेतावनी के बाद भी 10 जिलों ने जानकारी अपलोड नहीं की।



सिविल सेवा नियमों के तहत माना गया कदाचार

विभाग ने इसे घोर लापरवाही और मनमानी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। वेतन आहरण रोकने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

इन 19 जिलों के डीईओ पर गिरी गाज

रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और एमसीबी शामिल हैं। इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जिन्होंने दोनों श्रेणियों का डेटा ही नहीं भेजा।

जिले के धान खरीदी केंद्रों में पहुंची कलेक्टर ने कीं व्यवस्थाओं की पड़ताल

कृषकों से की चर्चा, तुंहर हाथ टोकन मोबाइल एप से टोकन प्रक्रिया का किया अवलोकन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो गई है। धान खरीदी के व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने धान उपार्जन केंद्र कृष्णपुर, देवनगर एवं चंदरपुर का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को किसानों की सुविधा, पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती जमील ने कहा कि धान विक्रय के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केंद्रों में पेयजल, बैठने एवं छांव की व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना, हमाल, तौल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। साथ ही खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने केंद्रों में नमी मापी यंत्र से धान की नमी की जांच कराई तथा स्वयं भी मशीन से नमी मापकर देखी। इसके अलावा धान की बोरियों का वजन कराकर निर्धारित मापदंड के अनुसार खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खराब बोरियों को स्वीकार नहीं करने तथा केंद्रों में साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरे, ऋण सूची एवं आवश्यक



सूचनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। कृष्णपुर केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे किसान हेमसाय राजवाड़े ने बताया कि वे 54 क्विंटल धान बेचने आए हैं। वहीं नारायणपुर के किसान श्री रामनरेश ने 100 क्विंटल धान का विक्रय किया। चंदरपुर समिति में भैयालाल, हंसलाल एवं रामजतन साहू सहित 19 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा।

कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता राशि की जानकारी भी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा गांव-गांव में मुनादी के माध्यम से किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं मोबाइल के माध्यम से शुंहर हाथश् टोकन एप पर टोकन काटने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और किसानों को डिजिटल माध्यम से टोकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

60 केंद्रों में 68,531 पंजीकृत किसान

जिले के 60 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 68,531 पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा एवं उपार्जन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में 6 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। पिछले दो दिन में जिले के 35 धान उपार्जन केन्द्रो में 300 किसानों से 12408 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी हैं। जिले में अवैध धान की आवक रोकने के लिए 04 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां अलग-अलग पालियों में निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी 09 तहसीलों में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। कोचियों-बिचौलियों तथा अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुनील अग्रवाल, जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मोहरसोप एवं नवगई धान खरीदी केंद्रों में पानी की व्यवस्था नहीं, प्यासे भटक रहे किसान

किसानों ने कलेक्टर से बोरिंग व सोलर पंप लगाने की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के मोहरसोप एवं नवगई धान खरीदी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन सैकड़ों किसान धान बेचने केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे आवश्यक पीने के पानी की सुविधा नहीं होने से उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।



छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। कलेक्टर द्वारा भी बैठकों में अधिकारियों को खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।मोहरसोप एवं नवगई धान खरीदी केंद्रों में रोजाना बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं। सुबह से शाम तक केंद्रों में किसानों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। किसानों ने सूरजपुर कलेक्टर से मांग की है कि दोनों धान खरीदी केंद्रों में तत्काल नवीन बोरिंग खनन कराकर सोलर ड्यूल पंप लगाया जाए, ताकि किसानों को पेयजल की सुविधा मिल सके।

स्वीकृत अवकाशों पर प्रतिबंधात्मक निर्देशों का आरोप, कलेक्टर को ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के शासकीय शिक्षकों के आकस्मिक, अर्जित, संतान पालन एवं अन्य स्वीकृत अवकाशों पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक निर्देशों को लेकर शिक्षक संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा, शिक्षकों के सेवा अधिकारों की बहाली तथा एचआरआईएमएस और व्हीएसके ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं वित्त विभाग तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को भी भेजी गई है। ज्ञापन सौपने वालो में जिलाध्यक्ष यादवेंद्र दुबे, गौतम शर्मा, राकेश गौतम, मुन्ना सोनी, अंकित कोसरिया, भागीरथी साहू, छोटेलाल ठाकुर और देवशरण सिंह उपस्थित रहे।



बेलटिकरी के 89 जनजातीय परिवारों के घर पहली बार पहुँची बिजली, लालटेन युग से मिली मुक्ति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में जिले में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में विकासखंड के ग्राम बेलटिकरी के 89 जनजातीय परिवारों के घरों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में इन सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन के प्रमाणपत्र वितरित किए गए। वर्षों से बिजली की सुविधा का इंतजार कर रहे इन परिवारों के घरों में रोशनी पहुंचने से ग्रामीणों को राहत मिली है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल द्वारा बेलटिकरी के विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। इसके तहत गांव में 218 विद्युत खंभे स्थापित किए गए। साथ ही 1.054 किलोमीटर 11 केवी हाईटेंशन लाइन एवं 7.657 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई गई। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए तथा सभी 89 परिवारों के घरों में मीटर लगाकर उन्हें विधिवत विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर संचालित अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर जीवन स्तर में सुधार लाना है।



गांव में बिजली पहुंचने से अब बच्चों को रात में भी पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। महिलाओं को घरेलू कार्यों में सहूलियत होगी तथा ढिबरी और लालटेन के धुएं से मुक्ति मिलेगी। वहीं मोबाइल, टीवी सहित अन्य विद्युत उपकरणों के उपयोग से ग्रामीण आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम में सरपंच रामबिलास सरुता, सचिव शिवशंकर गोयन, पंच दिनेश एवं मूलहदेव राजवाड़े, जनसाई एवं शिवलाल सहित विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता मुकेश कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता अनुरंजन कुजूर, शादाब अहमद एवं जी.एन. तिवारी सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे।

जिला जेल में हुआ विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां के जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हृदय नारायण श्रीवास्तव, अन्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। जेल में निरुद्ध निर्धन, दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा वित्तीय सहायता सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से गठित एंपावर्ड कमेटी के अंतर्गत यह निरीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



इस दौरान न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने जेल के विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से सीधे संवाद किया तथा उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन एवं अन्य समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विधिक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई बंदी आर्थिक अथवा अन्य कारणों से अपने खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पूरी टीम नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत है। जिन बंदियों के पास अपना अधिवक्ता नहीं है, वे अपनी आवश्यकता जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा जेल भ्रमण पर आने वाले लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं एवं लीगल एड क्लिनिक में उपलब्ध अधिवक्ताओं को बता सकते हैं। उन्होंने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, जमानत संबंधी प्रावधानों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि प्रथम बार अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में जमानत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता ली जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित बंदियों से उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं के संबंध में जानकारी लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक विधिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गिरदावली की त्रुटि से सैकड़ों किसान हो सकते है धान बेचने से वंचित

दावा-आपत्ति के बाद भी नहीं हुआ सुधार, कई किसानों का धान रकबा शून्य तो कई का एग्रीस्टेक रिकॉर्ड गायब

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में गिरदावली एवं एग्रीस्टेक रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण सैकड़ों किसानों के सामने धान बेचने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों द्वारा अक्टूबर माह में ही दावा-आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद अब तक रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया है। इससे किसान काफी परेशान हैं और समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित होने की आशंका जता रहे हैं। किसानों ने बताया कि उनके खेतों में धान की फसल लगी हुई है, लेकिन ऑनलाइन गिरदावली में कहीं अन्य फसल दर्ज कर दी गई है तो कहीं फसल का विवरण ही नहीं है। कई किसानों का धान का रकबा शून्य दर्ज हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई ऐसे किसान भी हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष शासन के धान खरीदी केंद्र में अपना धान बेचा था, लेकिन इस वर्ष गिरदावली में त्रुटि होने के कारण उनका धान का रकबा जीरो दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्हें इस वर्ष धान बेचने से वंचित रह जाने की चिंता सता रही है। वहीं कई किसानों का पिछले वर्ष एग्रीस्टेक रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन इस वर्ष उनका रिकॉर्ड गायब हो गया है। किसानों का कहना है कि इस समस्या को लेकर भी दो सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए कभी बिहारपुर तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके बावजूद गिरदावली एवं एग्रीस्टेक की त्रुटियों का सुधार नहीं हो पा रहा है। अक्टूबर महीने में दावा-आपत्ति करने और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। किसानों को डर है कि धान खरीदी की अवधि समाप्त होने से पहले यदि उनके रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ तो उनकी मेहनत से तैयार धान की उपज सरकारी खरीदी केंद्रों में नहीं बिक पाएगी।

कलेक्टर से तत्काल सुधार कराने की मांग

क्षेत्र के किसानों ने सूरजपुर कलेक्टर एवं जिला प्रशासन से पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेने की मांग की है। किसानों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश देकर खेतों का सत्यापन कराया जाए तथा गिरदावली में धान के रकबे, फसल विवरण और एग्रीस्टेक रिकॉर्ड की त्रुटियों को प्राथमिकता से सुधारा जाए, ताकि सैकड़ों किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न होना पड़े।



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
सामान्य वन मण्डल धरमजयगढ़ (छ.ग.)
ई-नीलाम विज्ञापन

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वन मंडल धरमजयगढ के काष्ठागार धरमजयगढ में उपलब्ध ईमारती एवं जलाऊ लकडी का दर्शित तिथि समय में ई-नीलाम किया जावेगा।

1. ई-नीलाम दिनांक – **23-11-2026**
2. ई-नीलाम समय – **प्रातः 09:00 बजे से प्रारंभ**

अ. क.	प्रजाति	नया वनोपज		पुराना वनोपज		योग वनोपज	
		लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	20.060	1075	104.766	--	**124.826**	**1075**
2	साल	56.258	601	2432.877	3072	**2489.135**	**3673**
3	बीजा	2.162	--	82.916	--	**85.078**	**--**
4	खम्हार	--	--	0.337	-	**0.337**	**-**
5	साजा	--	--	26.699	348	**26.699**	**348**
6	हल्दू	--	--	1.895	-	**1.895**	**-**
7	धावड़ा		--	8.083	128	**8.083**	**128**
8	सलिहा	--	--	7.915	-	**7.915**	**-**
9	अन्य	4.939	--	158.837	426	**163.776**	**426**
10	RTL	--	--	-	-	-	-
योग :–		**83.419**	**1676**	**2824.325**	**3974**	**2907.744**	**5650**
11	जलाऊ	99 चट्टा	–	4282 चट्टा	0	4381 चट्टा	–

अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे ई-नीलाम में भाग लेवें। ई-नीलाम की शर्ते व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय में डिपो से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त मात्रा में कमी-अधिकता संभव है।

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

जी-262704524/2

कुबेरपुर की चंद्रावती व संजय जायसवाल की मौत का मामला, समाज ने एसपी से निष्पक्ष जांच की उठाई मांग, बोले- स्थानीय नहीं जिला अधिकारियों से कराई जाए मामले की जांच

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के ग्राम कुबेरपुर की चंद्रावती और उनके पति संजय जायसवाल की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। दोनों की मौत को लेकर जायसवाल समाज ने गंभीर चिंता जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है। इस संबंध में जायसवाल समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने 17 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम कुबेरपुर निवासी चंद्रावती जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके पति संजय जायसवाल की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लगातार हुई इन दो घटनाओं ने परिवार के साथ-साथ समाज के लोगों को भी चिंतित कर दिया है। समाज ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर और संवेदनशील बताते हुए दोनों मौतों से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कराने की मांग की है। जायसवाल समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि चंद्रावती और संजय की मौत से जुड़े सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जाए। विशेष रूप से संजय जायसवाल की मौत के कारणों तथा मृत्यु से पूर्व किन लोगों द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ना



दिए जाने की बात सामने आई है, इसकी भी गहन पड़ताल की जाए। समाज ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी व्यक्ति की संलिप्तता या आपराधिक भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मांग यह भी रखी गई है कि जांच स्थानीय अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त रखते हुए जिला स्तर के अधिकारियों से निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, ताकि किसी प्रकार के दबाव या पक्षपात की आशंका न रहे। इसके अलावा पीड़ित परिवार, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

समाज ने जांच की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवार तथा समाज द्वारा नामित प्रतिनिधि को अवगत कराने की भी मांग रखी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि समाज का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है।

समाज ने पुलिस प्रशासन से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और दोनों मौतों के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा करने की मांग की है। इस दौरान रितेश जायसवाल, मिथलेश जायसवाल, नीरज गुप्ता, राकेश जायसवाल, संदीप गुप्ता, मौजूद रहे।

‘वोटर बचाओ-देश बचाओ’ सभा में भाजपा पर जमकर बरसे बैज

उदयपुर में कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, साल्ही में परसा कोल ब्लॉक का मुद्दा छाया

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। सरगुजा के उदयपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। ‘वोटर बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत उदयपुर रेस्ट हाउस के पास विशाल जनसभा हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे। सभा में भाजपा सरकार को महंगाई और मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर घेरा गया। इसके बाद साल्ही गांव में हुई चौपाल में परसा कोल ब्लॉक का मुद्दा गरमा गया।





रेस्ट हाउस के पास पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद हुई सभा में दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, बिजली के दाम और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ रहा है। कांग्रेस जनता के अधिकारों और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। सभा में नेताओं ने लोकतंत्र, मतदाता अधिकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। अदाणी समूह से जुड़े कोयला खनन और ऊर्जा क्षेत्र के सवाल भी भाषणों में उठे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, सिद्धार्थ सिंहदेव, ओम प्रकाश सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोजवंती सिंह समेत जिले और ब्लॉक के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने उठाया फर्जी ग्रामसभा का मुद्दा

उदयपुर की सभा के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला कोल प्रभावित गांव साल्ही पहुंचा। वहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। यहां सबसे ज्यादा चर्चा परसा कोल ब्लॉक को लेकर हुई। ग्रामीण रामलाल करियाम ने नेताओं के सामने आरोप लगाया कि परसा कोल ब्लॉक फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव के आधार पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को रद्द कराने के लिए कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां और लंबे समय से लंबित मांगें नेताओं के सामने रखीं।

प्रदेश प्रभारी ने कहा-लड़ेंगे कानूनी लड़ाई

इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने पास मौजूद दस्तावेज कांग्रेस नेताओं को दें, ताकि पूरे मामले को वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा जा सके। दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। ग्रामीणों ने भी समय पर दस्तावेज देने की बात कही। साल्ही की चौपाल के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की चुप्पी भी चर्चा में रही।

सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म का कर रही है नाकाबिल इस्तेमाल

‘वोटर बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में हो रही समस्या, पंजीयन नहीं होना, एग्री स्टैक नहीं हो पाना और राशन कार्ड कटने की स्थिति, ये सब एक ही कारण से बन रही है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाकाबिल तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर वोट कट रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में बाबा ने कहा कि जब सरकार वोट काटकर चुनाव जीत जाएगी, तो उसे लोगों का काम करने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। फिर स्कूल क्यों देखना, फिर हाथी की तरफ ध्यान क्यों देना, फिर किसानों के धान की बात क्यों करना। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर, लोगों को जागरूक करने सभी नेता निकले हैं।

मत की रक्षा से ही राशन और बिजली बिल की रक्षा

टीएस सिंहदेव ने कहा कि अपने मत की रक्षा करने से ही राशन की व्यवस्था की रक्षा होगी। उसी से बढ़ी हुई बिजली बिल की दरों में कमी आ सकती है। अगर सरकार को लगेगा कि हम तो जीत ही जाएंगे, 50 साल हम ही रहेंगे, 100 साल हम ही रहेंगे, तो यही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वही मुद्दे आज जमीन पर दिख रहे हैं। वोट कटने से लेकर राशन कटने तक, किसान की परेशानी से लेकर आम आदमी की परेशानी तक, सब जुड़ा हुआ है। किसानों को धान बेचने में समस्या हो रही है। पंजीयन नहीं हो पा रहा है, एग्री स्टैक नहीं हो पा रहा है। कितने लोगों का राशन कटने की स्थिति बन रही है। धान उठाने में जो दिक्कत हो रही है, वो भी इसी परिस्थिति में बनती है।

सरकार फेल, बच्चे अधिकारियों के पास जा रहे

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बच्चे अब अपने स्कूलों और छात्रावासों से निकलकर अधिकारियों के पास अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है। शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में 33, 34, 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। विधानसभा में कही गई बात एक कमिटमेंट होती है, सरकार के लिए एक बंधन होता है। बावजूद इसके अभी तक वैसी भर्ती देखने को नहीं मिली।

1000 से ज्यादा स्कूल बंद, गुणवत्ता टूटी

सिंहदेव ने कहा कि अभी तो हजार से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जब शिक्षा की गुणवत्ता टूटेगी तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की स्थिति बनेगी। बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास लगता नहीं है कि राशियां हैं। प्रबंधन इतना कमजोर है कि सड़कों की हालत देखिए क्या है। बिल्डिंग की स्थिति आप कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। यानी हर मोर्चे पर सरकार का प्रबंधन फेल नजर आ रहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

टीएस बाबा ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर ही सरकार ध्यान नहीं देगी, तो आम आदमी का क्या होगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए, मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, यह सरकार की नाकामी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार को लगेगा कि वोट से ही जवाब मिलेगा, तभी वह काम करेगी। नहीं तो यही स्थिति बनी रहेगी।

शंकरघाट बेरियर में 97 नग नशीली इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर पकड़ाए



छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीले इंजेक्शन खपाने की फिराक में पहुंचे दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में एक अन्य मेडिकल दुकान के संचालक के विरूद्ध भी केस दर्ज किया है, जो पलामू झारखंड का रहने वाला है।

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली पुलिस को 16 नवंबर को शाम 4.40 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि डिगमा में ठिकाना बनाया अंकित गुप्ता अपने साथी साहिद अंसारी के साथ नशीला इंजेक्शन बेचने शंकरघाट खनिज बेरियर के पास आने वाला है। सूचना पर सउनि देवनारायण यादव के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की। मौके पर दोनों संदेहियों की तलाशी लेने पर इनके पास कार्टून डिब्बे में अलग-अलग नाम का 97 नग इंजेक्शन मिला, जिसकी कीमत 97 हजार रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने यह इंजेक्शन हिसराब बाड़ी के एक मेडिकल दुकान संचालक से खरीदा था। पुलिस ने अंकित गुप्ता पिता रामनाथ गुप्ता 27 वर्ष, मूल निवासी जैसिंहनगर शहडोल मध्य प्रदेश, हाल मुकाम डिगमा एफसीआई गोदाम के पीछे अंबिकापुर और साहिद अंसारी पिता मुमताज अंसारी 25 वर्ष, निवासी ग्राम दिनाबार, रामगढ़, पलामू, झारखंड को रात 9.50 बजे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मेडिकल दुकान संचालक के विरूद्ध भी केस दर्ज किया है, और उसके भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक अनुराग वर्मा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा, हिमांशु दास, लाल बाबू सिंह, शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।

पटवारियों के समर्थन में आगे आया फेडरेशन, आक्रोश रैली आज



छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले में पटवारी संघ के आंदोलन को अब बड़ा समर्थन मिलने लगा है। पटवारियों की मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन भी आगे आ गया है। इधर मंगलवार को अंबिकापुर में राजस्व निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय अवकाश लेकर धरना स्थल पर एकत्र होकर अपना समर्थन दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद धरना स्थल से कलेक्टोरेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रैली में शामिल कर्मचारियों ने पटवारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई को निरस्त करने, आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण करने और प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग की। इसी क्रम में 18 अक्टूबर को वृहद रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के सदस्य मौजूद रहे।

राजस्व निरीक्षक संघ ने दिया समर्थन

पटवारी संघ की मांगों के समर्थन में राजस्व निरीक्षक संघ के सरगुजा अध्यक्ष और उप प्रांताध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वे एक दिवसीय अवकाश लेकर पटवारियों की मांगों के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने कहा सरकार दमनात्मक कार्रवाई की जगह पटवारियों के हित में सकारात्मक निर्णय ले। शासन की सोच पटवारियों का काम राजस्व निरीक्षकों से लेने की है, जो उचित नहीं है। पटवारी और राजस्व निरीक्षक एक ही परिवार हैं, हम एक-दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इसी तारतम्य में पटवारियों के खिलाफ हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। फेडरेशन के आह्वान पर कल 18 नवंबर को प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। संघ ने पीवी ऐप का बहिष्कार करते हुए वेतन विसंगति दूर करने के साथ-साथ हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए 140 से अधिक पटवारियों की बहाली और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

अंधेरे में खड़ी टीपर से भिड़े बाइक सवार की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। टीपर वाहन से भिड़ंत और मोटरसायकल सवार के द्वारा मारी गई टक्कर में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भकुरा का उमेश्वर राजवाड़े पिता स्व. मोहन राम 39 वर्ष के यहां 16 नवम्बर को मेहमान आए थे। इन्हें छोड़ने के लिए अपने मोटरसायकल में पेट्रोल भरवाने उमेश्वर अपने गांव से ग्राम रजपुरी जाने के लिए निकला था। पेट्रोल पम्प पहुंचने के पहले ही मुख्य मार्ग में अंधेरे में खड़ी गिट्टी लोड टीपर वाहन क्रमांक सीजी 15 डीएन 2701 से उसको जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। संजीवनी 108 एम्बुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। घायल को भर्ती कराने के बाद एक पुलिसकर्मी ने फोन करके स्वजन को बताया कि मोबाइलधारक का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी स्थिति गंभीर है। इन्हें जिला अस्पताल अंबिकापुर आने के लिए कहा गया। स्वजन अस्पताल पहुंचे तो आपातकालीन चिकित्सा परिसर में घायल युवक स्ट्रेचर में बेसुध हाल में पड़ा था। जांच के बाद चिकित्सक ने 11.40 बजे उसे मृत घोषित कर दिया।

बाइक को मारी टक्कर, घायल महिला की मौत

दूसरे मामले में पति के साथ मोटरसायकल वाहन में मायके से लौट रहे दंपती को पीछे से आ रहे मोटरसायकल सवार ने ठोकर मार दिया। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई थी। जशपुर जिला के बगीचा थाना अंतर्गत ग्राम नवाटोली निवासी मुन्ना राम ने पुलिस को बताया वह अपनी पत्नि राजकुमारी 30 वर्ष, अपने भजीता के साथ मोटरसायकल से ग्राम सेमरडांड ससुराल गया था। वापस घर आते समय अपरान्ह करीब 3 बजे महादेवडांड बादूपारा चौक के पास अज्ञात मोटरसायकल का चालक पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें उसकी पत्नि फेंका गई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। गंभीर स्थिति में घायल पत्नि को स्वास्थ्य केन्द्र महादेवडांड ले गया, प्राथमिक उपचार के बाद रिफर करने पर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां सोमवार को शाम करीब 5.30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का 3 दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू

मांगें पूरी नहीं हुई तो जाएंगी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, जिला इकाई सरगुजा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ ने कलेक्टर सरगुजा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी और समस्त परियोजना अधिकारियों को पत्र लिखकर धरना-प्रदर्शन की सूचना दी है।



संघ का कहना है कि लगातार समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी मांग की पूर्ति और समस्या का निराकरण नहीं किया गया। इसी से नाराज होकर अब चरणबद्ध धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रथम चरण में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक 03 दिवसीय जिला स्तरीय चरणबद्ध ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन, द्वितीय चरण में 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 02 दिवसीय प्रांत स्तरीय महापड़ाव प्रमुख है। संघ ने चेतावनी दी है कि उक्त धरना प्रदर्शन के बाद भी जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी। इनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, नियमितीकरण करते तक कार्यकर्ता व सहायिकाओं को 30 हजार रुपये मानदेय देना व आयु सीमा में छूट प्रदान कर कार्यकर्ताओं को 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों में परीक्षा न लेकर तत्काल 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति देना शामिल है। संघ की जिला अध्यक्ष भुनेश्वरी सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुलोचना राजवाड़े, जिला सचिव सपना सिंह के नेतृत्व में जिले की कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाया है, और जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति एवं समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

ऑनलाइन टोकन से आसान हुई धान बिक्री, रामपुर केंद्र में 826 किसानों को मिली सुविधा

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया धान खरीदी का शुभारंभ

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान बिक्री की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले के रामपुर धान खरीदी केंद्र में सात ग्राम पंचायतों के 826 पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इस केंद्र से रामपुर, चिताबहार, सरईटिकारा, नावांबांध, पोड़ी, हरिहरपुर और परसोडी ग्राम पंचायतों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

धान खरीदी का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया। इस दौरान किसानों में अपनी उपज बेचने को लेकर उत्साह देखने को मिला। धान खरीदी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप सुविधा किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। अब किसान घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से धान बिक्री का टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इससे उन्हें टोकन के लिए उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और वे अपनी सुविधा के अनुसार धान बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं।

बेटे ने घर बैठे काटा टोकन

ग्राम रामपुर निवासी किसान भुवनेश्वर राम राजवाड़े के पास लगभग सवा एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने मोबाइल से ऑनलाइन टोकन कटवाया, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिली। वे 22 क्विंटल धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र में धान खरीदी की व्यवस्था अच्छी है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होने से खेती-बाड़ी के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के लिए घर बैठे टोकन की सुविधा उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है।

धान बेचने पहुंचे इतबल राम

ग्राम पोड़ी खुर्द निवासी किसान इतबल राम ने भी ‘तुंहर टोकन’ ऐप की सुविधा का लाभ लिया। उन्होंने अपने भतीजे के मोबाइल से घर बैठे ही 20 क्विंटल धान बिक्री का टोकन प्राप्त किया। उनके पास कुल 64 क्विंटल धान का रकबा है। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र में बारदाना उपलब्ध हो गया है और धान की तौलाई भी व्यवस्थित तरीके से हो रही है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इतबल राम ने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होने से खेती-किसानी के कार्यों में मदद मिल रही है। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र

आदिमजाति सेवा सहकारी समिति केंद्र रामपुर में सात ग्राम पंचायतों के 826 पंजीकृत किसान अपनी उपज का विक्रय कर रहे हैं। ऑनलाइन टोकन सुविधा, बारदाना की उपलब्धता और सुव्यवस्थित तौलाई जैसी व्यवस्थाओं से किसानों को धान बिक्री में सहूलियत मिल रही है। शासन की इन व्यवस्थाओं से किसानों का समय बच रहा है और वे बिना अनावश्यक भागदौड़ के अपनी उपज का विक्रय कर पा रहे हैं।

गौ अष्टमी पर गौ आश्रय धाम में उमड़ी श्रद्धा, विधि-विधान से हुआ गौ माता का पूजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। दीपावली के आठ दिन बाद मनाए जाने वाला गौ अष्टमी का पर्व सरगुजा जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खलीबा स्थित गौ आश्रय धाम में सैकड़ों की संख्या में गौ प्रेमी पहुंचे। यहां विधि-विधान से गौ माता की पूजा-अर्चना की गई और गौवंशों को आहार खिलाकर सेवा एवं समर्पण का संदेश दिया गया। गौ अष्टमी के अवसर पर गौ आश्रय धाम में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने गौ माता का पूजन कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन के दौरान गौ सेवा और गौ संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष रिंकू तिवारी ने बताया कि गौ आश्रय धाम पिछले कई वर्षों से बेसहारा और जरूरतमंद गौवंशों की सेवा एवं संरक्षण के कार्य में जुटा हुआ है। संस्था के अनुसार अब तक सरगुजा जिले में 30 हजार से अधिक गायों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस अवसर पर गौ आश्रय धाम में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे गौ प्रेमियों और पशु प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में शामिल सरोज मिश्रा ने भी गौ माता का पूजन करके अपनी श्रद्धा प्रकट की। गौ अष्टमी का यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गौवंशों के प्रति सेवा, संवेदना और संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी देता नजर आया।



विधायक ने धान समिति अध्यक्षों की ली वर्चुअल बैठक, सीएम का जताया आभार

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई किसान उन्नति योजना को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और खुशहाली की दिशा में बड़ा कदम है। विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी शुरू होते ही विधायक रामकुमार टोप्पो ने सक्रियता दिखाते हुए सभी धान खरीदी समिति केंद्रों के अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में उन्होंने एक-एक केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की और किसानों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छाया, टोकन वितरण की पारदर्शी और क्रमबद्ध प्रक्रिया हर केंद्र पर सुनिश्चित हो। किसानों का सम्मान और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस पर मेरी निरंतर निगरानी बनी रहेगी। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लगातार सहयोग दे रही है, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार भी किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसान उन्नति योजना इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे सीधे किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। उन्होंने सीतापुर विधानसभा के समस्त किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के सम्मान और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।



स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर